भारतीय अर्थव्यवस्था नोट्स

परिचय-अर्थव्यवस्था

- ए.जे. ब्राउन ने अर्थव्यवस्था शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है, "एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका कमाते हैं।" जे.आर. हिक्स ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है, "अर्थव्यवस्था उत्पादकों और श्रमिकों का सहयोग है जो उपभोक्ताओं की इच्छाओं को पूरा करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं।"
- अर्थशास्त्र विषय को दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र।
- 'माइक्रो इकोनॉमिक्स' और 'मैक्रो इकोनॉमिक्स' शब्दों का पहली बार अर्थशास्त्र में इस्तेमाल नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिस्क ने 1933 में किया था।
- जॉन मेनार्ड कीन्स को मैक्रोइकॉनॉमिक्स का जनक माना जाता है

वृहद अर्थशास्त्र

- अर्थशास्त्र की वह शाखा जो समग्र रूप से किसी अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है
- यह राष्ट्रीय उत्पादन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और करों जैसे समुच्चयों का अध्ययन है
- कीन्स द्वारा प्रकाशित रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है।

व्यष्टि अर्थशास्त्र

- सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे घरों, फर्मों या उद्योगों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है।

AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE BUREAUCRATS
WITH IGNITED MINDS

आर्थिक प्रणाली

- आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें व्यक्ति और संस्थाएँ किसी विशेष क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए एक साथ जुड़ती हैं। यह समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक गतिविधियाँ करने की पद्धति है

• आर्थिक प्रणालियाँ **तीन प्रमुख प्रकार की** होती हैं :

1. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
2. समाजवादी अर्थव्यवस्था
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था

<u>पूंजीवादी अर्थव्यवस्था</u>

- एडम स्मिथ 'पूंजीवाद के जनक' हैं।
- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है जहां सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है और बाजार आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करता है।
- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं। निर्माता लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। निजी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने और कोई भी कौशल विकसित करने की स्वतंत्रता होती है।
- अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के सर्वोत्तम उदाहरण हैं

समाजवादी अर्थव्यवस्था

- समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं।
- समाजवाद को समाज को संगठित करने के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रमुख उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को 'नियोजित अर्थव्यवस्था' या 'कमांड अर्थव्यवस्था' के रूप में भी जाना जाता है
- समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का स्वामित्व और संचालन सरकार के पास होता है। सभी आर्थिक गतिविधियों के पीछे जन कल्याण ही मुख्य उद्देश्य होता है
- इसका उद्देश्य आय और धन के वितरण में समानता और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना है
- चीन, वियतनाम, पोलैंड और क्यूबा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। लेकिन, अब कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतः समाजवादी नहीं है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था

- मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में रहते हैं और आर्थिक विकास के लिए मिलकर काम करते हैं
- इन अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों का स्वामित्व व्यक्तियों और सरकार के पास होता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण: भारत, इंग्लैंड, फ्रांस और ब्राजील

AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE CIVIL SERVANTS
WITH IGNITED MINDS

राष्ट्रीय आय

• राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का व्यापक माप प्रदान करती है । यह देश की क्रय शक्ति को दर्शाता है। किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को उस दर से मापा जाता है जिस पर समय के साथ उसकी वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ती है।

- इस प्रकार राष्ट्रीय आय आर्थिक नियोजन के साधन के रूप में कार्य करती है।
- राष्ट्रीय आय का अर्थ है 'किसी विशेष अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य'

राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएँ

- राष्ट्रीय आय को मापने में प्रयुक्त कुछ अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं।

1. **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)**
2. **शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी)**
3. **सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी)**
4. **शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी)**
5. **कारक लागत पर एनएनपी**
6. **व्यक्तिगत आय**
7. **प्रयोज्य आय**
8. **प्रति व्यक्ति आय**
9. **वास्तविक आय**
10. **जीडीपी डिफ्लेटर**

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। भारत के लिए, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
- क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी)

- शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी) जीडीपी है जिसकी गणना 'मूल्यह्रास' के मूल्य के भार को समायोजित करने के बाद की जाती है।

एनडीपी = जीडीपी - मूल्यह्रास।

- किसी अर्थव्यवस्था का एनडीपी हमेशा उसी वर्ष के जीडीपी से कम होना चाहिए

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी)

- जीएनपी एक वर्ष के दौरान किसी देश में चालू उत्पादन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का कुल माप है, जिसमें विदेशों से शुद्ध आय भी शामिल है
- सामान्य सूत्र है जीएनपी = जीडीपी + विदेश से आय

{(विदेश से आय= व्यापार संतुलन + विदेशी ऋण पर ब्याज+ निजी धन प्रेषण) निजी धन प्रेषण= निजी हस्तांतरण के कारण अंतर्वाह और बहिर्वाह

व्यापार संतुलन = वर्ष के अंत में कुल आयात और निर्यात का शुद्ध परिणाम।

बाह्य ऋणों पर ब्याज = ब्याज भुगतान के अंतर्वाह का शेष – ब्याज भुगतान का बहिर्वाह}

- भारत के मामले में, यह हमेशा नकारात्मक रहा है (व्यापार घाटे और विदेशी ऋणों पर ब्याज भुगतान के कारण भारी बहिर्वाह के कारण)। इसका मतलब है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद से 'विदेश से आय' को घटाकर उसकी जीएनपी की गणना की जाती है।

जीएनपी = जीडीपी + (–विदेश से आय)

(भारत का जीएनपी हमेशा उसके जीडीपी से कम होता है)

- बाजार मूल्य पर जीएनपी का अर्थ है किसी देश में प्रतिवर्ष उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी)

- किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी) 'मूल्यह्रास' के कारण होने वाली हानि को घटाने के बाद का सकल राष्ट्रीय उत्पाद है।

एनएनपी = जीएनपी – मूल्यह्रास

या

एनएनपी = जीडीपी + विदेश से आय - मूल्यह्रास।

- यह किसी राष्ट्र की आय का सबसे शुद्ध रूप है।

कारक लागत पर एनएनपी

- एनएनपी उत्पादन के बाजार मूल्य को संदर्भित करता है। जबकि कारक लागत पर एनएनपी उत्पादन के कारकों को किए गए आय भुगतान का योग है। इस प्रकार बाजार मूल्य पर एनएनपी के मौद्रिक मूल्य से, हम अप्रत्यक्ष करों की राशि घटाते हैं और सब्सिडी जोड़ते हैं, जिससे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है।

कारक लागत पर एनएनपी = बाजार मूल्य पर एनएनपी - अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी।

व्यक्तिगत आय

- व्यक्तिगत आय एक वर्ष में प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पहले सभी स्रोतों से किसी देश के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल आय है

व्यक्तिगत आय = राष्ट्रीय आय– (सामाजिक सुरक्षा योगदान और अवितरित कॉर्पोरेट लाभ) + हस्तांतरण भुगतान

प्रयोज्य आय

- डिस्पोजेबल आय को डिस्पोजेबल व्यक्तिगत आय के रूप में भी जाना जाता है। यह आयकर के भुगतान के बाद व्यक्ति की आय है

प्रयोज्य आय = व्यक्तिगत आय – प्रत्यक्ष कर प्रति व्यक्ति आय

- किसी देश के एक व्यक्ति की किसी विशेष वर्ष में औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त की जाती है

प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय/जनसंख्या वास्तविक आय

- नाममात्र आय एक विशेष वर्ष के सामान्य मूल्य स्तर के संदर्भ में व्यक्त राष्ट्रीय आय है, दूसरे शब्दों में, वास्तविक आय नाममात्र आय की क्रय शक्ति है।
- वास्तविक आय मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद व्यक्तियों या राष्ट्रों की आय है

जीडीपी डिफ्लेटर

- जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तनों का एक सूचकांक है। यह एक मूल्य सूचकांक है जिसकी गणना किसी दिए गए वर्ष में नाममात्र जीडीपी को उसी वर्ष के वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और उसे 100 से गुणा करके की जाती है।

जीडीपी डिफ्लेटर = नाममात्र जीडीपी / वास्तविक जीडीपी x 100

सकल मूल्य वर्धन

- सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) किसी क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के सेक्टर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है।

जीवीए = जीडीपी + सब्सिडी - (प्रत्यक्ष, बिक्री) कर।

राष्ट्रीय आय की लागत और कीमत लागत

- कारक लागत- किसी अर्थव्यवस्था में फर्मों और उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर वास्तविक व्यय को कारक लागत के रूप में जाना जाता है। यानी, पूंजी की लागत, ऋण पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली, आदि।
- बाजार लागत- 'बाजार लागत' अप्रत्यक्ष करों को उत्पाद की कारक लागत में जोड़ने के बाद प्राप्त होती है, इसका मतलब है वह लागत जिस पर माल बाजार तक पहुंचता है
- भारत आधिकारिक तौर पर अपनी राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत पर करता था। जनवरी 2015 से, CSO ने राष्ट्रीय आय की गणना बाजार लागत पर करना शुरू कर दिया है। बाजार मूल्य की गणना कारक लागत में उत्पाद करों को जोड़कर की जाती है

कीमत

- आय दो कीमतों पर प्राप्त की जा सकती है, स्थिर और चालू। स्थिर और चालू कीमतों में अंतर केवल मुद्रास्फीति के प्रभाव का है

वर्तमान मूल्य = स्थिर मूल्य + मुद्रास्फीति

क्रय शक्ति समता

- क्रय शक्ति से संबंधित एक अवधारणा क्रय मूल्य समता (पीपीपी) है। पीपीपी एक आर्थिक सिद्धांत है जो उस राशि का अनुमान लगाता है जिसे किसी वस्तु के मूल्य में समायोजित करने की आवश्यकता होती है
- पीपीपी का उपयोग देशों के आय स्तर और जीवन-यापन की लागत, या मुद्रास्फीति और अपस्फीति की संभावित दरों से संबंधित अन्य प्रासंगिक आर्थिक आंकड़ों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है।
- क्रय मूल्य समता (पीपीपी) के मामले में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

- किसी देश/अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को मोटे तौर पर तीन मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और उनके प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को उनके नाम भी मिलते हैं।

प्राथमिक क्षेत्र

- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए होने वाली आर्थिक गतिविधियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कृषि गतिविधियाँ, खनन, तेल अन्वेषण आदि।
- जब कृषि क्षेत्र (प्राथमिक क्षेत्र के उप-क्षेत्र) किसी देश में राष्ट्रीय आय और आजीविका में न्यूनतम आधे का योगदान करते हैं तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

द्वितीयक क्षेत्र

- इसमें वे सभी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं जिनके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से निकाले गए कच्चे माल को संसाधित किया जाता है (इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है)।
- जब द्वितीयक क्षेत्र किसी देश में राष्ट्रीय आय और आजीविका का न्यूनतम आधा हिस्सा लाता है तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

तृतीयक क्षेत्र:

- सभी आर्थिक गतिविधियाँ जहाँ सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इस क्षेत्र में आती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, संचार, आदि।
- जब यह क्षेत्र किसी देश में राष्ट्रीय आय और आजीविका में न्यूनतम आधे का योगदान देता है तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE BUREAUCRATS
WITH IGNITED MINDS

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

- भारतीय अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में विभाजित है

1. **प्राथमिक क्षेत्र: (कृषि क्षेत्र)** कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं। कृषि आधारित सहायक गतिविधियाँ, कच्चे माल का उत्पादन जैसे मवेशी पालन, मछली पालन, खनन, वानिकी, मक्का, कोयला आदि भी किए जाते हैं।

2. **द्वितीयक क्षेत्र: (औद्योगिक क्षेत्र)** औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र है जिसमें कच्चे माल को परिवर्तित करके वस्तुओं और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। महत्वपूर्ण उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा, जूट, चीनी, सीमेंट, कागज, पेट्रोकेमिकल उद्योग, ऑटोमोबाइल और अन्य लघु उद्योग हैं।

3. **तृतीयक क्षेत्र: (सेवा क्षेत्र)** तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जिसमें सरकार, वैज्ञानिक अनुसंधान, परिवहन संचार, व्यापार, डाक और तार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल और सूचना प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

- भारत कृषि उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कुल वैश्विक कृषि उत्पादन में भारत का योगदान 7.39 प्रतिशत है
- वर्तमान में भारतीय जीडीपी संरचना इस प्रकार है: कृषि (16.5%), उद्योग (29.01%) और सेवाएं (53.09%)।
- देश की सकल आय में कृषि का हिस्सा घटता जा रहा है, जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आजीविका के लिहाज से अभी भी भारत के 48.7 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं
- कार्यबल द्वारा क्षेत्र हिस्सेदारी: (कृषि (48%): तृतीयक (27%): द्वितीयक (24%))
- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान विश्व के औसत (6.4%) से कहीं अधिक है। उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान विश्व के औसत से कम है - उद्योग क्षेत्र के लिए 30% और सेवा क्षेत्र के लिए 63%।
- भारत नाममात्र जीडीपी के हिसाब से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

भारत में कृषि क्षेत्र

- भारत में कृषि सर्वाधिक अपनाया जाने वाला व्यवसाय है, तथा इसकी अर्थव्यवस्था में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- देश की सकल आय में कृषि का हिस्सा घटता जा रहा है, जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आजीविका के दृष्टिकोण से अभी भी भारत के 48.7 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। इससे कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।
- कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, जो कुल असंगठित श्रम-बल में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है (भारत की 94 प्रतिशत से अधिक कार्यशील आबादी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है)
- भारत वैश्विक कृषि व्यापार में अग्रणी स्थान रखता है, जिसकी विश्व कृषि व्यापार में 2.15 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- कृषि न केवल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है, बल्कि देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र भी है।
- हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति और जैव प्रौद्योगिकी के आविष्कारों ने कृषि को आत्मनिर्भर बना दिया है और अधिशेष उत्पादन भी किया है

- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'सात सूत्री रणनीति' की घोषणा की है। 'सात सूत्री रणनीति' का विवरण नीचे दिया गया है

1. सिंचाई पर ध्यान केन्द्रित करना तथा 'प्रति बूंद, अधिक फसल' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े बजट का प्रावधान करना।
2. मृदा स्वास्थ्य के आधार पर गुणवत्तापूर्ण बीज और पोषक तत्वों का प्रावधान।
3. कटाई के बाद फसल की हानि को रोकने के लिए भंडारण और शीत श्रृंखला को मजबूत करना।
4. खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
5. राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण, विकृतियों को दूर करना और ई-प्लेटफॉर्म।
6. उपयुक्त प्रकार के कृषि बीमा के माध्यम से किफायती लागत पर जोखिम को कम करना।
7. मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन और मत्स्यपालन जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

भारतीय रिजर्व बैंक

- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
- रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया
- ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे
- आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था

प्रशासन

- आरबीआई के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं: उत्तर के लिए नई दिल्ली, दक्षिण के लिए चेन्नई, पूर्व के लिए कोलकाता और पश्चिम के लिए मुंबई
- केंद्रीय बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - राज्यपाल
  - 4 उप गवर्नर
  - 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
  - स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 निदेशक जिनका मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में होगा
- केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ गवर्नर और 4 उप गवर्नर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

- एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर थे, मनमोहन सिंह थे।
- रिजर्व बैंक को 'मिंट स्ट्रीट' नाम से भी जाना जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक प्राधिकरण के कार्य

- यह विनिमय दर को स्थिर करने, भुगतान संतुलन को स्वस्थ बनाए रखने, वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है

मुद्रा जारीकर्ता

- इसका उद्देश्य देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को बनाए रखना है। यह मुद्रा जारी करने का एकमात्र प्राधिकरण है (एक रुपये या उसके मूल्यवर्ग की मुद्रा और सिक्कों को छोड़कर, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं)। यह नकली मुद्रा के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए भी कार्रवाई करता है।

बैंकिंग लाइसेंस जारीकर्ता

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक बैंक को भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

बैंकर्स बैंक

- आरबीआई भारत में सभी बैंकों का बैंक है क्योंकि यह बैंकों को ऋण प्रदान करता है, बैंकों की जमा स्वीकार करता है, और बैंकों के बिलों की पुनर्भुनाई करता है।

सरकार का बैंकर

- यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यह सरकारी ऋणों के सभी नए मुद्दों का प्रबंधन करता है, बकाया सरकारी ऋण की सेवा करता है और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार का पोषण करता है।
- यह सरकार को बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर सलाह देता है।

आखिरी कर्जदाता

- बैंक जरूरत या संकट के समय, जब कोई अन्य स्रोत न हो, पात्र प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं।

क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करें

- बैंकिंग लेनदेन के निपटान के लिए, RBI 14 क्लियरिंग हाउस का प्रबंधन करता है। यह उपकरणों के आदान-प्रदान और भुगतान निर्देशों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है।

विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक

- आरबीआई विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों को प्रशासित और लागू करता है।

- आरबीआई विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा खरीदता और बेचता है। देश के विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार को बनाए रखना
- आरबीआई आईएमएफ और विश्व बैंक (और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों, जिनका भारत सदस्य है) में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।

अर्थव्यवस्था का नियामक

- यह प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जीडीपी, मुद्रास्फीति आदि जैसे विभिन्न प्रमुख संकेतकों पर नज़र रखता है।

भुगतान और निपटान प्रणालियों का नियामक और पर्यवेक्षक

- भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (पीएसएस अधिनियम) आरबीआई को देश में भुगतान एवं निपटान प्रणालियों की निगरानी का अधिकार देता है।
- आरबीआई सुरक्षित, संरक्षित और कुशल भुगतान और निपटान तंत्र के विकास और कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसका उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना है।

बैंकिंग लोकपाल योजना

- आरबीआई ने 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, शिकायतकर्ता ऑनलाइन सहित किसी भी रूप में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और बैंकों के निर्णयों और अन्य निर्णयों के खिलाफ लोकपाल के समक्ष अपील भी कर सकते हैं।

मौद्रिक डेटा और अन्य डेटा का प्रकाशक

- RBI सभी आवश्यक बैंकिंग और अन्य आर्थिक डेटा रखता है और प्रदान करता है, भारत में आर्थिक नीतियों का निर्माण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। RBI नियमित रूप से डेटा एकत्र करता है, उनका मिलान करता है और उन्हें प्रकाशित करता है

विकासात्मक कार्य

- इस भूमिका में भारत में गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग प्रणाली का विकास करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध हो। यह राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए प्रचार कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
- इसमें देश के वित्तीय ढांचे के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना भी शामिल है। इस भूमिका को निभाते हुए, RBI ने IDBI, SIDBI, NABARD, NEDB (उत्तर पूर्वी विकास बैंक), एक्ज़िम बैंक, NHB जैसे विकासात्मक बैंकों की स्थापना की।

मौद्रिक नीति

- मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग से है, जिसका उद्देश्य आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्याज दरों, धन की आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिमाणों को विनियमित करना है।

- मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिए निर्धारित की जाने वाली व्यापक आर्थिक नीति है।

- यह मांग पक्ष आर्थिक नीति है जिसका उपयोग किसी देश की सरकार द्वारा मुद्रास्फीति, खपत, विकास और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

- मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों का उपयोग किया जाता है। ये हैं नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और खुले बाजार परिचालन।

- धारा 45जेडबी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है।

- मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं

1. धन की तटस्थता
2. विनिमय दरों की स्थिरता
3. मूल्य स्थिरता
4. पूर्ण रोजगार
5. आर्थिक विकास
6. भुगतान संतुलन में संतुलन

ऋण नियंत्रण उपाय

- ऋण नियंत्रण मौद्रिक प्रबंधन के उद्देश्यों को साकार करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए उपलब्ध प्राथमिक तंत्र है

- रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण प्रणाली पर नियंत्रण का वैधानिक आधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निहित है।

ऋण नियंत्रण के तरीके

- सामान्य या मात्रात्मक विधियाँ

1. बैंक दर 2. खुले बाजार परिचालन 3. परिवर्तनीय नकद आरक्षित अनुपात

- चयनात्मक या गुणात्मक विधियाँ

1. ऋण की राशनिंग 2. प्रत्यक्ष कार्रवाई 3. नैतिक दबाव 4. प्रचार 5. उपभोक्ता ऋण का विनियमन 6. सीमांत आवश्यकताएं

मात्रात्मक या सामान्य विधियाँ

1. बैंक दर नीति

- आरबीआई द्वारा दीर्घकालिक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर के रूप में जाना जाता है।
- इस दर का भारतीय वित्तीय प्रणाली में कार्यरत संबंधित ऋणदाता निकायों की दीर्घकालिक ऋण गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- उदाहरण: यदि केंद्रीय बैंक ऋण को नियंत्रित करना चाहता है, तो वह बैंक दर बढ़ा देगा। परिणामस्वरूप, मुद्रा-बाजार में जमा दर और अन्य उधार दरें बढ़ जाएंगी। उधार लेना हतोत्साहित होगा, और ऋण में संकुचन होगा और इसके विपरीत।

2. खुले बाजार परिचालन

- संकीर्ण अर्थ में, केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शुरू करता है
- व्यापक अर्थ में, केंद्रीय बैंक न केवल सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है, बल्कि निजी संस्थाओं के बिल और प्रतिभूतियों जैसी अन्य उचित पात्र प्रतिभूतियों की भी खरीद और बिक्री करता है। जब बैंक और निजी व्यक्ति इन प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, तो उन्हें इन प्रतिभूतियों के लिए केंद्रीय बैंक को भुगतान करना होता है।

3. परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात , नकद आरक्षित अनुपात

- मौद्रिक नीति के उद्देश्य के रूप में परिवर्तनीय नकद आरक्षित अनुपात का सुझाव सबसे पहले जेएम कीन्स ने दिया था
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) नकदी की वह राशि है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखनी होती है
- वाणिज्यिक बैंकों को कानून के अनुसार अपनी मांग जमा और केंद्रीय बैंक के पास सावधि जमा के आधार पर भंडार बनाए रखना होता है जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है
- यदि सीआरआर अधिक है, तो वाणिज्यिक बैंक की ऋण सृजन क्षमता कम होगी और यदि सीआरआर कम है, तो वाणिज्यिक बैंक की ऋण सृजन क्षमता अधिक होगी।

4. वैधानिक तरलता अनुपात

- वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वह राशि है जिसे बैंक को नकदी, सोना या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। यह राशि बैंक की कुल मांग और सावधि देनदारियों के कुछ प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट की जाती है।
- एसएलआर का उपयोग ऋण विस्तार के लिए बैंक के उत्तोलन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

5. रेपो दर और रिवर्स रेपो दर

- रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं जिनके साथ आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की उपलब्धता और आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। भारत में रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है

AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE BUREAUCRATS
WITH IGNITED MINDS

रेपो दर

- रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
- रेपो दर का उपयोग मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

रिवर्स रेपो दर

- जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेने को तैयार है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है
- रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति या तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है।

कॉल मनी मार्केट

- कॉल मनी मार्केट, मनी मार्केट का एक महत्वपूर्ण खंड है जहां रातोंरात आधार पर धन उधार लिया और दिया जाता है
- कॉल मनी मार्केट में भागीदार आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट बैंक और संबंधित संस्थाएं हैं। भारत में कॉल मनी मार्केट में प्रतिभागियों में वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), सहकारी बैंक (भूमि विकास बैंकों के अलावा), प्राथमिक डीलर (पीडी) शामिल हैं।
- इस बाजार में एक दिन के लिए उधार दिए जाने वाले पैसे को कॉल मनी कहा जाता है और अगर यह एक दिन से ज़्यादा हो तो इसे नोटिस मनी कहा जाता है। नोटिस मनी का मतलब 2-14 दिनों के लिए पैसे उधार लेना और उधार देना है।

आरबीआई का नया वित्तीय वर्ष

- अपने वित्तीय वर्ष को सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से, फरवरी 2020 में, आरबीआई ने 2020-21 से अपने नए वित्तीय वर्ष के रूप में अप्रैल-मार्च को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया (अपने मौजूदा वित्तीय वर्ष जुलाई-जून से)।

AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE BUREAUCRATS
WITH IGNITED MINDS

भारत में बैंकिंग

बैंकिंग

- बैंकिंग क्षेत्र आधुनिक व्यापार जगत की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
- भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान (1770) था

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

- स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास को अपनाया। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण था। स्वतंत्रता से पहले वाणिज्यिक बैंक निजी क्षेत्र में थे। ये वाणिज्यिक बैंक नियोजन के सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करने में विफल रहे। इसलिए सरकार

ने 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। 1980 में फिर से सरकार ने 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का अधिग्रहण कर लिया।

राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य

1. राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण प्राप्त करना था। कृषि, लघु और ग्रामीण उद्योग जैसे क्षेत्रों को अपने विस्तार और आगे के आर्थिक विकास के लिए धन की आवश्यकता थी।

2. बैंकों के राष्ट्रीयकरण से निजी एकाधिकार पर अंकुश लगाने में मदद मिली, ताकि सामाजिक रूप से वांछनीय वर्गों को ऋण की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

3. राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराईं।

4. क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था, जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

वाणिज्यिक बैंक

• वाणिज्यिक बैंक से तात्पर्य किसी बैंक या किसी बड़े बैंक के एक प्रभाग से है, जो अधिक विशिष्ट रूप से निगमों या बड़े/मध्यम आकार के व्यवसायों को प्रदान की जाने वाली जमा और ऋण सेवाओं से संबंधित है - जो कि जनता/छोटे व्यवसाय के व्यक्तिगत सदस्यों के विपरीत है।

वाणिज्यिक बैंकों के कार्य

• वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को मोटे तौर पर प्राथमिक कार्यों और द्वितीयक कार्यों में वर्गीकृत किया जाता है

<u>प्राथमिक कार्य</u>

1. जमा स्वीकार करना

• इसका तात्पर्य यह है कि वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से सार्वजनिक जमा पर निर्भर हैं।

• जमाराशि दो प्रकार की होती है, जिनकी चर्चा इस प्रकार की गई है

o डिमांड डिपॉजिट: यह उन जमाराशियों को संदर्भित करता है जिन्हें व्यक्ति बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के निकाल सकता है। दूसरे शब्दों में, इन जमाराशियों के मालिकों को बैंक काउंटर पर या डेबिट कार्ड का उपयोग करके एटीएम केंद्र से निकासी पर्ची या चेक लिखकर कभी भी पैसे निकालने की अनुमति है।

o सावधि जमा: यह उन जमाओं को संदर्भित करता है जो निश्चित अवधि के लिए किए जाते हैं। बैंक सावधि जमा पर अधिक ब्याज देते हैं। इन जमाओं को बैंक को लिखित सूचना देकर एक निश्चित समय अवधि के बाद ही निकाला जा सकता है।

2. ऋण अग्रिम करना

• इसका तात्पर्य व्यक्तियों और व्यवसायों को ऋण प्रदान करना है। वाणिज्यिक बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद ऋण और विनिमय बिलों में छूट के रूप में ऋण प्रदान करते हैं।

<u>द्वितीयक कार्य</u>

1. एजेंसी कार्य

• इसका तात्पर्य यह है कि वाणिज्यिक बैंक विभिन्न कार्य करके ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं

o चेक एकत्र करना: बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदान की गई क्लियरिंग हाउस सुविधाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों की ओर से चेक और विनिमय बिल एकत्र करते हैं।

o आय एकत्र करना: वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों की ओर से लाभांश, पेंशन, वेतन, किराया और निवेश पर ब्याज एकत्र करते हैं। जब बैंक द्वारा कोई आय एकत्र की जाती है तो ग्राहकों को जानकारी के लिए क्रेडिट वाउचर भेजा जाता है।

o व्यय का भुगतान: वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों के विभिन्न दायित्वों का भुगतान करते हैं, जैसे टेलीफोन बिल, बीमा प्रीमियम, स्कूल फीस और किराया। क्रेडिट वाउचर की तरह, डेबिट वाउचर ग्राहकों को जानकारी के लिए भेजा जाता है जब बैंक द्वारा व्यय का भुगतान किया जाता है।

2. धन हस्तांतरण

• यह एक बैंक से दूसरे बैंक में धन के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। धन का हस्तांतरण ड्राफ्ट, टेलीफोनिक हस्तांतरण और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

3. ऋण पत्र

• वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को उनकी ऋण पात्रता प्रमाणित करने के लिए ऋण पत्र जारी करते हैं ।

o प्रतिभूतियों का हामीदारी: वाणिज्यिक बैंक प्रतिभूतियों का हामीदारी का कार्य भी करते हैं। चूंकि जनता को बैंकों की साख पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए जनता बैंकों द्वारा हामीदारी की गई प्रतिभूतियों को खरीदने में संकोच नहीं करती।

o इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग: इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं।

3. सामान्य उपयोगिता कार्य

• इसका तात्पर्य यह है कि वाणिज्यिक बैंक विभिन्न कार्य करके ग्राहकों को कुछ उपयोगी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

o विदेशी मुद्रा में लेनदेन: वाणिज्यिक बैंक निर्यात और आयात में कारोबार करने वाले व्यापारियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। हालाँकि, वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है।

o लॉकर सुविधा प्रदान करना: वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को आभूषण, शेयर, डिबेंचर और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लॉकर सुविधा प्रदान करते हैं। इससे घरों में चोरी के कारण होने वाले नुकसान का जोखिम कम हो जाता है। लॉकर में रखी वस्तुओं के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं हैं।

अन्य कार्य

1. मुद्रा आपूर्ति

- यह वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जो मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने में मदद करता है

2. ऋण सृजन

- ऋण सृजन का अर्थ है ऋण और अग्रिमों का गुणन। वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा प्राप्त करते हैं और इन जमाओं का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं। हालाँकि, दिए जाने वाले ऋण बैंकों द्वारा प्राप्त जमा राशि से कई गुना अधिक होते हैं। बैंकों के इस कार्य को 'ऋण सृजन' के रूप में जाना जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) पहली बार 2 अक्टूबर, 1975 को स्थापित किए गए थे (संख्या केवल 5 थी)

- आरआरबी की स्थापना **नरसिम्हम समिति** कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत क्षेत्रीय आधारित ग्रामीण ऋण संस्थानों के रूप में आरआरबी की स्थापना की गई थी।

- भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक राष्ट्रीयकृत बैंक क्रमशः 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत के अनुपात में आरआरबी की शेयर पूंजी का योगदान करते हैं। आरआरबी का परिचालन क्षेत्र राज्य के कुछ अधिसूचित जिलों तक सीमित है।

- **पहला आरआरबी: प्रथमा ग्रामीण बैंक**

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आरआरबी को अपने कुल ऋण का 75 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत प्रदान करना है।

- आरआरबी का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों का विकास हो सके।

लघु एवं भुगतान बैंक

- 2014 में आरबीआई ने छोटे बैंकों और पेमेंट बैंकों की स्थापना के लिए मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए थे। दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि दोनों ही 'विशिष्ट' या 'विभेदित' बैंक हैं जिनका साझा उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

लघु वित्त बैंक

- लघु वित्त बैंक भारत में एक प्रकार के विशिष्ट बैंक हैं। लघु वित्त बैंक लाइसेंस वाले बैंक जमा स्वीकार करने और उधार देने की बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकते हैं। इनके पीछे उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उन वर्गों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना है जिन्हें अन्य बैंकों द्वारा सेवा नहीं दी जा रही है, जैसे कि लघु व्यवसाय इकाइयाँ, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र की इकाइयाँ

भुगतान बैंक

- भुगतान बैंकों का उद्देश्य सुरक्षित प्रौद्योगिकी-संचालित वातावरण में जमा और भुगतान/प्रेषण सेवाओं में उच्च मात्रा-कम मूल्य के लेनदेन को सक्षम करके प्रवासी श्रमिकों, कम आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों,

अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को लघु बचत खाते, भुगतान/प्रेषण सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।

- भुगतान बैंक मांग जमा (केवल चालू खाता और बचत खाता) स्वीकार कर सकते हैं। उन्हें शुरू में प्रति ग्राहक अधिकतम 1 लाख रुपये तक की राशि रखने की अनुमति होगी। प्रदर्शन के आधार पर, RBI इस सीमा को बढ़ा सकता है।
- भुगतान बैंकों को अन्य बैंकों से अलग पहचान बनाने के लिए अपने नाम में 'भुगतान' शब्द का प्रयोग करना होगा।
- भुगतान बैंकों को ऋण देने की अनुमति नहीं है।
- भुगतान बैंक गठन - नचिकेत मोर समिति

सहकारी बैंक

- भारत में बैंकों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है - वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। जबकि वाणिज्यिक बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक समूह, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय बैंक) ग्रामीण बैंकों) का बैंकिंग कारोबार में बड़ा हिस्सा है, सहकारी बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इसे दो व्यापक खंडों में विभाजित किया जा सकता है: i) शहरी सहकारी बैंक ii) ग्रामीण सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक

- शहरी सहकारी बैंक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हैं।
- शहरी सहकारी बैंकों की बैंकिंग गतिविधियों की निगरानी आरबीआई द्वारा की जाती है। पंजीकरण और प्रबंधन गतिविधियों का प्रबंधन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) द्वारा किया जाता है। ये आरसीएस एकल-राज्य में संचालित होते हैं और केंद्रीय आरसीएस (सीआरसीएस) कई राज्यों में संचालित होते हैं।

ग्रामीण सहकारी बैंक

- ग्रामीण सहकारी बैंक अल्पकालिक और दीर्घकालिक संरचनाएं हैं।
- अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना तीन-स्तरीय प्रणाली के साथ संचालित होती है

1. राज्य सहकारी बैंक: राज्यों में शीर्ष स्तर पर कार्य करते हैं
2. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक: जिला स्तर पर कार्य करते हैं
3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ: गाँव या जमीनी स्तर पर संचालित होती हैं

मुद्रा (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी)

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक योजना है।

- इन ऋणों को PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।

- इसके अंतर्गत डिज़ाइन किए गए उत्पादों को वित्त की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम हैं शिशु (50,000 रुपये तक का ऋण), किशोर (50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक) और तरुण (5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक)।

- इस योजना का उद्देश्य छोटे उधारकर्ताओं को ऋणदाताओं द्वारा दिए गए संपार्श्विक-मुक्त ऋणों को पुनर्वित्त करना है

- यद्यपि यह योजना फलों और सब्जियों के व्यापारियों को कवर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर यह कृषि क्षेत्र को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करती है।

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) एनबीएफसी

- गैर-बैंक वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) एक वित्तीय संस्था है जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है या जिसकी निगरानी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं की जाती है।

- एनबीएफसी को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात (1) स्टॉक एक्सचेंज; और (2) अन्य वित्तीय संस्थान। बाद की श्रेणी में वित्त कंपनियाँ, वित्त निगम, चिट फंड, बिल्डिंग सोसायटी, इश्यू हाउस, निवेश ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट तथा बीमा कंपनियाँ आती हैं।

- यह कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी है

- यह ऋण और अग्रिम, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी बांड/डिबेंचर/प्रतिभूतियों या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, पट्टे, किराया-खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय के व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी सामान की खरीद या बिक्री या कोई सेवा प्रदान करना और अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद है।

- इसमें चालू और बचत खातों की तरह मांग जमा नहीं हो सकती

नाबार्ड (कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक)

- नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी. शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी

- जुलाई 1982 में संसद के एक अधिनियम द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में एआरडीसी के कार्यों और आरबीआई के पुनर्वित्तपोषण कार्यों को अपने हाथ में लेना था।

- नाबार्ड, आरबीआई के साथ जैविक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरबीआई अपनी आधी शेयर पूंजी का योगदान देता है, जबकि शेष आधी भारत सरकार द्वारा योगदान की जाती है।

- आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

नाबार्ड के कार्य

- नाबार्ड एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प तथा वास्तविक कारीगरों और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए सभी प्रकार के उत्पादन और निवेश ऋण के लिए पुनर्वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।

- यह राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), आरआरबी, एलडीबी और आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है

- नाबार्ड के पास केन्द्र और राज्य सरकारों, नीति आयोग और अन्य अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी है, जिन्हें लघु उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण शिल्प, छोटे और विकेन्द्रित क्षेत्रों में उद्योग आदि के विकास का काम सौंपा गया है।

- प्राथमिक सहकारी समितियों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का निरीक्षण करना इसकी जिम्मेदारी है।

- यह कृषि और ग्रामीण विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अनुसंधान और विकास कोष बनाए रखता है

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

- देश की अब तक वंचित बड़ी आबादी तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाकर वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा इसकी विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) शुरू की गई।

धन

- मौद्रिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो मुद्रा और विनिमय के माध्यम, मूल्य के भंडार और लेखांकन की इकाई के रूप में इसके कार्यों का विश्लेषण करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

- धन वह चीज़ है जिसे आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है और जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है।

मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास

- मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में पेश करना मानव जाति के सबसे महान आविष्कारों में से एक था। मुद्रा के आविष्कार से पहले, विनिमय वस्तु-विनिमय द्वारा होता था, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए सीधे आदान-प्रदान किया जाता था।

- खाल, नमक, चावल, गेहूँ, बर्तन, हथियार आदि जैसी वस्तुओं का आमतौर पर मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। वस्तुओं के बदले वस्तुओं के इस तरह के आदान-प्रदान को "वस्तु विनिमय प्रणाली" के रूप में जाना जाता था।

- वस्तु विनिमय प्रणाली मेसोपोटामिया जनजातियों द्वारा शुरू की गई थी

धातु मानक

- धातु मानक के तहत, पैसे और मुद्रा के मानक मूल्य को निर्धारित करने के लिए सोने या चांदी के साथ किसी प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। उनका अंकित मूल्य उनके आंतरिक धातु मूल्य के बराबर होता है।

स्वर्ण - मान

- गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मौद्रिक इकाई या मानक मुद्रा का मूल्य सीधे सोने से जुड़ा होता है। मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति सोने के एक निश्चित वजन के मूल्य के बराबर रखी जाती है।

रजत मानक

- चांदी मानक एक मौद्रिक प्रणाली है जिसमें लेखांकन की मानक आर्थिक इकाई चांदी का एक निश्चित वजन है

कागजी मुद्रा मानक

- कागजी मुद्रा मानक से तात्पर्य उस मौद्रिक प्रणाली से है जिसमें ट्रेजरी या सेंट्रल बैंक या दोनों द्वारा जारी किए गए कागजी मुद्रा नोट असीमित कानूनी निविदा के रूप में प्रचलन में रहते हैं। इसका मूल्य सोने या किसी अन्य वस्तु के मूल्य से स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है।

- मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा प्रचलन में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है।

प्लास्टिक मनी

- पैसे का नवीनतम प्रकार प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी वित्तीय उत्पादों के सबसे विकसित रूपों में से एक है।

- प्लास्टिक मनी कई अलग-अलग रूपों में आ सकती है जैसे कैश कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, स्टोर कार्ड, फॉरेक्स कार्ड और स्मार्ट कार्ड

क्रिप्टो करेंसी

- एक डिजिटल मुद्रा जिसमें मुद्रा की इकाइयों के निर्माण को विनियमित करने और धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। उदाहरण: बिटकॉइन

AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE BUREAUCRATS
WITH IGNITED MINDS

महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

<u>बंजर धन</u>

- वह धन जिस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा हो
- वह धन जो कहीं निवेशित न हो
- सुरक्षित जमा लॉकर में रखा गया धन

<u>फिएट मनी</u>

- फिएट मनी वह है जिसे वैध मुद्रा घोषित किया जाता है। इसमें प्रचलन में मौजूद किसी भी तरह की मुद्रा जैसे कि कागजी मुद्रा या सिक्के शामिल हैं। फिएट मनी को भौतिक वस्तु के बजाय देश की सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है।

धन की आपूर्ति

- मुद्रा आपूर्ति का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा। यह किसी भी समय अर्थव्यवस्था में प्रचलन में मौजूद मुद्रा की मात्रा को संदर्भित करता है।
- मूल्य स्तर और ब्याज दरों के निर्धारण में मुद्रा आपूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
- भारत में, करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए जाते हैं और सिक्के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी किए जाते हैं।
- मुद्रा आपूर्ति के निर्धारक

1. मुद्रा जमा अनुपात (सीडीआर)
2. आरक्षित जमा अनुपात (आरडीआर)
3. नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)
4. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)

मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र

मुद्रा स्फ़ीति

- मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर में एक निरंतर और सराहनीय वृद्धि है। दूसरे शब्दों में, मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ रहा है और परिणामस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति गिर रही है।
- मुद्रास्फीति की दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है जो दो प्रकार के होते हैं- थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)।

मुद्रास्फीति के प्रकार (मांग और आपूर्ति के आधार पर)

मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति

- समाज में हर समय मुद्रास्फीति के स्तर को तय करने में मांग और आपूर्ति की अहम भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी उत्पाद की मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है, तो उस उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है

लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति:

- जब कच्चे माल और अन्य इनपुट की लागत बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति होती है। श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन में वृद्धि से भी मुद्रास्फीति होती है।

मुद्रास्फीति के प्रकार (गति के आधार पर)

धीमी मुद्रास्फीति या कम मुद्रास्फीति:

- बढ़ती मुद्रास्फीति धीमी गति से चलती है और बहुत हल्की होती है। कीमतों में वृद्धि प्रत्यक्ष नहीं होगी, बल्कि लंबे समय तक फैली रहेगी।

- कम मुद्रास्फीति या धीमी मुद्रास्फीति लंबी अवधि में होती है और वृद्धि की सीमा आमतौर पर 'एकल अंक' में होती है।

- इस प्रकार की मुद्रास्फीति किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक नहीं है। इसे हल्की मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है

चलती मुद्रास्फीति:

- जब कीमतें सामान्य रूप से बढ़ती हैं और वार्षिक मुद्रास्फीति दर एकल अंक (3% - 9%) होती है, तो इसे वॉकिंग या ट्रोलिंग मुद्रास्फीति कहा जाता है।

चलित मुद्रास्फीति:

- जब कीमतें घोड़े की तरह तेजी से 10% - 20% प्रति वर्ष की गति से बढ़ती हैं, तो इसे चलती मुद्रास्फीति कहा जाता है

तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति:

- यह 'बहुत उच्च मुद्रास्फीति' है जो दोहरे अंक या तिहरे अंक (एक वर्ष में 20%, 100% और 200%) की सीमा में चल रही है।

अति मुद्रास्फीति:

- मुद्रास्फीति का यह रूप 'बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला' है, जिसकी वार्षिक दर मिलियन या ट्रिलियन में भी हो सकती है। ऐसी मुद्रास्फीति में न केवल वृद्धि की सीमा बहुत बड़ी होती है, बल्कि वृद्धि बहुत ही कम समय में होती है, कीमतें रातोंरात बढ़ जाती हैं।

मुद्रास्फीति के प्रकार (प्रेरणा के आधार पर)

ऋण मुद्रास्फीति

- जब बैंक ऋण देने में उदारता दिखाते हैं, तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ जाती हैं।

मुद्रा मुद्रास्फीति

- प्रचलन में मुद्रा की अधिक आपूर्ति के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि होती है।

- इस प्रकार की मुद्रास्फीति करेंसी नोटों की छपाई के कारण होती है

घाटे से प्रेरित मुद्रास्फीति

- घाटे के बजट का वित्तपोषण आम तौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा छापने के माध्यम से किया जाता है। परिणामस्वरूप, कीमतें बढ़ जाती हैं

कर प्रेरित मुद्रास्फीति

- उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी और बिक्री कर जैसे अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि हो सकती है (उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल)। इसे कर प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है।

अभाव प्रेरित मुद्रास्फीति

- वस्तुओं की कमी या तो उत्पादन में कमी (जैसे कृषि उत्पाद) या जमाखोरी और कालाबाज़ारी के कारण होती है। इससे भी कीमतें बढ़ जाती हैं।

लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति

- जब कंपनियां अधिक लाभ कमाने का लक्ष्य रखती हैं, तो वे अधिक मार्जिन के साथ कीमत तय करती हैं। इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं

मुद्रास्फीति के कारण

मुद्रास्फीति के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि

- मुद्रास्फ़ीति मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण होती है जिससे कुल मांग में वृद्धि होती है। नाममात्र मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर जितनी अधिक होगी, मुद्रास्फीति की दर उतनी ही अधिक होगी।

उपभोक्ता व्यय में वृद्धि

- जब किराया-खरीद और किस्त के आधार पर सामान खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है।

निर्यात में वृद्धि

- जब निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, तो वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति कम हो जाती है। इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं।

सार्वजनिक ऋण की चुकौती

- जब भी सरकार जनता को अपना पिछला आंतरिक ऋण चुकाती है, तो इससे जनता के पास मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग में वृद्धि होती है।

घाटे का वित्तपोषण

- घाटे के वित्तपोषण से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

- घाटा व्यय और प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। सार्वजनिक वित्त में, इसका मतलब है कि सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर रही है। घाटे के वित्तपोषण के कारण धन की आपूर्ति बढ़ जाती है और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है। इससे कुल आपूर्ति के संबंध में कुल मांग बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।

सस्ते पैसे की नीति

- सस्ती मुद्रा नीति का अर्थ है व्यापार और उद्योग को सस्ती ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराना

- सस्ती मुद्रा नीति से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है

प्रयोज्य आय में वृद्धि

- डिस्पोजेबल आय को डिस्पोजेबल व्यक्तिगत आय के रूप में भी जाना जाता है। यह आयकर के भुगतान के बाद व्यक्ति की आय है

प्रयोज्य आय = व्यक्तिगत आय – प्रत्यक्ष कर

- जब लोगों की प्रयोज्य आय बढ़ती है, तो इससे वस्तुओं और सेवाओं की उनकी मांग बढ़ जाती है।

काली संपत्ति, गतिविधियाँ और धन

- भ्रष्टाचार, कर चोरी आदि के कारण काले धन और काली संपत्तियों का अस्तित्व कुल मांग को बढ़ाता है। लोग इस पैसे को खुलेआम खर्च करते हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी से वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाती है। ये प्रवृत्तियाँ मूल्य स्तर को और अधिक बढ़ा देती हैं।

मुद्रास्फीति के प्रभाव

देनदारों और लेनदारों पर:

- मुद्रास्फीति के दौरान, देनदार लाभ में होते हैं जबकि लेनदार घाटे में होते हैं। इसका कारण यह है कि देनदारों ने उस समय उधार लिया था जब मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक थी और अब वे ऋण तब चुका रहे हैं जब बढ़ती कीमतों के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम है।

- विपरीत प्रभाव तब होता है जब मुद्रास्फीति कम हो जाती है (अर्थात, अपस्फीति)।

रोजगार पर

- मुद्रास्फीति अल्पावधि में रोजगार बढ़ाती है, लेकिन दीर्घावधि में तटस्थ या नकारात्मक हो जाती है

आयात पर

- मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को कम आयात और आयात प्रतिस्थापन का लाभ देती है क्योंकि विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। लेकिन अनिवार्य आयात (यानी, तेल, प्रौद्योगिकी, दवाएँ, आदि) के मामले में अर्थव्यवस्था को यह लाभ नहीं मिलता है और बचत करने के बजाय अधिक विदेशी मुद्रा खो देता है।

- मुद्रास्फीति विनिमय दरों को बढ़ाती है और सभी आयातों को महंगा बनाती है

निर्यात पर

- मुद्रास्फीति के कारण, किसी अर्थव्यवस्था की निर्यात योग्य वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होता है। इसके कारण, निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में निर्यात आय बढ़ जाती है।

- मुद्रास्फीति की उच्च दर अर्थव्यवस्था में निर्यात उद्योग को बुरी तरह प्रभावित करेगी। उत्पादन की लागत बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।

- मुद्रास्फीति किसी देश के आयात और निर्यात पर भारी प्रभाव डाल सकती है

व्यापार संतुलन पर

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मामले में मुद्रास्फीति व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाती है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति उनके व्यापार संतुलन के लिए प्रतिकूल है। ऐसा उनके विदेशी व्यापार की संरचना के कारण होता है।
- यदि अनिवार्य आयात अधिक है तो मुद्रास्फीति नुकसानदायक हो सकती है

निश्चित आय समूह

- मुद्रास्फीति के दौरान निश्चित आय वाले समूह सबसे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आय निश्चित होने के कारण जीवन की बढ़ती लागत से कोई संबंध नहीं रखती है। उदाहरण के लिए वेतन, पेंशन, ब्याज, किराया आदि।

निवेशकों

- निवेशक, जो आम तौर पर निश्चित ब्याज देने वाले बॉन्ड और प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, मुद्रास्फीति के दौरान बहुत कुछ खो देते हैं। इसके विपरीत जो लोग शेयरों में निवेश करते हैं, वे शेयरों के मूल्य में वृद्धि और भरपूर लाभांश के माध्यम से लाभ कमाते हैं।

उत्पादन पर प्रभाव

- जब मुद्रास्फीति बहुत मध्यम होती है, तो यह व्यापारियों और उत्पादकों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। बढ़ती कीमतों के कारण होने वाला लाभ व्यापारी वर्ग को उत्पादन में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है, जिससे रोजगार और आय का सृजन होता है

विनिमय दर पर

- उच्च मुद्रास्फीति दर वाली मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और उसका मूल्य कम हो जाता है, जबकि कम मुद्रास्फीति दर वाली मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ जाता है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

1. मौद्रिक उपाय
2. राजकोषीय उपाय
3. अन्य उपाय.

मौद्रिक उपाय

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति है।

(i) बैंक दर में वृद्धि
(ii) खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
(iii) उच्च नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)
(iv) उपभोक्ता ऋण नियंत्रण
(v) उच्च मार्जिन आवश्यकताएं

(vi) उच्च रेपो दर और रिवर्स रेपो दर।

- मौद्रिक नीति केवल मांग-प्रेरित कारकों के कारण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है।

राजकोषीय उपाय

- राजकोषीय नीति को अब मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी गई है।
- प्रमुख मुद्रास्फीति-रोधी राजकोषीय उपाय निम्नलिखित हैं:

1. सरकारी व्यय में कमी
2. सार्वजनिक उधार
3. कराधान में वृद्धि.
4. अधिशेष बजट
5. बचत में वृद्धि

अन्य उपाय

1. उत्पादन बढ़ाना · मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक उत्पादन बढ़ाना है

2. मजदूरी और मूल्य नियंत्रण · मजदूरी और मूल्य नियंत्रण मूल्य वृद्धि के साथ मजदूरी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

अपस्फीति

- अपस्फीति की अनिवार्य विशेषता कीमतों में गिरावट, मुद्रा आपूर्ति में कमी और बेरोजगारी है। हालांकि मुद्रास्फीति के समय कीमतों में गिरावट वांछनीय है, लेकिन ऐसी गिरावट से उत्पादन और रोजगार के स्तर में गिरावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर कीमतें पूर्ण रोजगार के स्तर से गिरती हैं तो आय और रोजगार दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी

- मुद्रास्फीतिजनित मंदी स्थिर आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति का संयोजन है।

विस्फीति

- डिस्इन्फ्लेशन का मतलब है, बिना अधिक बेरोजगारी पैदा किए उपभोक्ताओं को उपलब्ध ऋण की मात्रा को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति की दर को धीमा करना। डिस्इन्फ्लेशन को बेरोजगारी पैदा किए बिना या अर्थव्यवस्था में उत्पादन को कम किए बिना मुद्रास्फीति को उलटने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है

भारत में मुद्रास्फीति

- भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना **दो मूल्य सूचकांकों पर करता है** ; ये हैं

1. **थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)**
2. **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)।**

• **थोक मूल्य सूचकांक साप्ताहिक आधार** पर मापा जाता है । भारत में थोक मूल्यों का **पहला सूचकांक 10 जनवरी, 1942** के सप्ताह के लिए शुरू हुआ था । **थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष समय-समय पर संशोधित किया जाता** है । **वर्तमान** थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष **2011-12 है जो 697 वस्तुओं** की कीमतों पर आधारित है ।

• भारत थोक मूल्यों के अलावा उपभोक्ता मूल्यों पर भी मुद्रास्फीति को मापता रहा है। लेकिन एकल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्थान पर भारत उपभोक्ताओं के बीच पाए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक विभेदों के कारण सीपीआई के चार अलग-अलग सेटों के साथ काम चला रहा है। ये हैं: सीपीआई-आईडब्ल्यू (औद्योगिक कर्मचारी), सीपीआई-यूएनएमई (शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारी), सीपीआई-आरएल (ग्रामीण मजदूर) और सीपीआई-एएल (कृषि मजदूर)।

व्यापार चक्र

• पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इन उतार-चढ़ावों के अध्ययन को व्यापार चक्र या व्यापार चक्र या औद्योगिक उतार-चढ़ाव का अध्ययन कहा जाता है।

व्यापार चक्र का अर्थ

• व्यापार चक्र समग्र आर्थिक गतिविधि में उतार-चढ़ाव को संदर्भित करता है, विशेष रूप से रोजगार, उत्पादन, आय आदि में। यह उन तत्वों के अंतर्निहित संकुचन और विस्तार के कारण होता है जो राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करते हैं। उतार-चढ़ाव आवधिक होते हैं, तीव्रता में भिन्न होते हैं और इसके कवरेज में परिवर्तन होता है।

• व्यापार चक्र के चार अलग-अलग चरणों को कहा जाता है

(i) बूम
(ii) मंदी
(iii) अवसाद और
(iv) वसूली

AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE BUREAUCRATS
WITH IGNITED MINDS

बूम

• आर्थिक गतिविधियों में तीव्र ऊर्ध्वगामी उतार-चढ़ाव को तेजी कहा जाता है।

• पूर्ण रोजगार और पूर्ण रोजगार से परे अर्थव्यवस्था की गति को तेजी की अवधि के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस अवधि के दौरान, अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक गतिविधि होती है। मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है, मुनाफा बढ़ता है और ब्याज दरें बढ़ती हैं। बैंक ऋण की मांग बढ़ती है और चौतरफा आशावाद होता है।

मंदी

• तेजी की स्थिति से मोड़ आने को मंदी कहते हैं। यह पहले की तुलना में अधिक दर पर होता है। आम तौर पर, किसी कंपनी या बैंक की विफलता तेजी को रोकती है और मंदी का दौर लाती है। निवेश में भारी कमी आती है, उत्पादन कम हो जाता है और आय और लाभ में गिरावट आती है। शेयर बाजार में घबराहट

होती है और व्यापारिक गतिविधियों में सुस्ती के संकेत दिखाई देते हैं। लोगों की तरलता वरीयता बढ़ जाती है और मुद्रा बाजार तंग हो जाता है।

अवसाद

- मंदी के दौरान आर्थिक गतिविधि का स्तर बेहद कम हो जाता है। कंपनियों को घाटा होता है और कारोबार बंद होना आम बात हो जाती है और इसका अंतिम परिणाम बेरोजगारी होता है। ब्याज दरें, मुनाफा और मजदूरी कम होती है। कृषि वर्ग और वेतनभोगी वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बैंकिंग संस्थान व्यवसायियों को ऋण देने में अनिच्छुक होंगे।

- मंदी व्यापार चक्र का सबसे बुरा चरण है। मंदी के चरम बिंदु को "गर्त" कहा जाता है, क्योंकि यह व्यापार चक्र का सबसे गहरा बिंदु होता है। कीन्स ने वकालत की कि अकेले सरकार का स्वायत्त निवेश अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर आने में मदद कर सकता है।

वसूली

- यह मंदी से पुनरुत्थान की ओर बढ़ने का मोड़ है। इसकी शुरुआत पूंजीगत वस्तुओं की मांग के पुनरुद्धार से होती है। स्वायत्त निवेश गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। मांग धीरे-धीरे बढ़ती है और समय के साथ गतिविधि अधिक उत्पादन, लाभ, आय, मजदूरी और रोजगार के साथ उछाल की ओर निर्देशित होती है। सुधार नवाचार या निवेश या सरकारी व्यय द्वारा शुरू किया जा सकता है ।

भारत में आर्थिक नियोजन

- आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक निश्चित समयावधि के भीतर आर्थिक विकास के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है

- भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में राष्ट्रीय योजना आयोग के गठन और मिश्रित आर्थिक प्रणाली की नीति के विस्तार का सुझाव दिया गया था।

भारत में नियोजन का विकास नीचे बताया गया है:

- **सर एम. विश्वेश्वरय्या (1934):** एक प्रमुख इंजीनियर और राजनीतिज्ञ ने 1934 में अपनी पुस्तक, "प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया" के माध्यम से भारत में आर्थिक नियोजन की नींव रखने का पहला प्रयास किया। यह 10 वर्षीय योजना थी।

- **जवाहरलाल नेहरू (1938):** एक समिति द्वारा "राष्ट्रीय योजना आयोग" की स्थापना की गई, लेकिन राजनीतिक युग में परिवर्तन और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह अमल में नहीं आ सका।

- **बॉम्बे योजना (1940):** बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने "बॉम्बे योजना" प्रस्तुत की। यह 15 वर्षीय निवेश योजना थी।

- **एस. एन. अग्रवाल (1944) ने** कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए " **गांधीवादी योजना " दी।**

- **एमएन रॉय (1945) ने ' पीपुल्स प्लान** ' का मसौदा तैयार किया। इसका उद्देश्य केवल राज्य द्वारा कृषि उत्पादन और वितरण का मशीनीकरण करना था।

- **जेपी नारायण (1950)** ने " **सर्वोदय योजना** " की वकालत की जो **गांधीवादी योजना** और **विनोबा भावे के विचार** से **प्रेरित थी** । इसने न केवल कृषि को महत्व दिया, बल्कि योजना में लघु और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया।

योजना आयोग

- भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी
- योजना आयोग का गठन 15 मार्च, 1950 को हुआ तथा योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल, 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के शुभारंभ के साथ हुई।
- जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे
- 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ

- भारत में आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है
- भारत ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजनाओं में अंतिम थी
- भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

- यह योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
- इसका मुख्य फोकस देश के कृषि विकास पर था।
- भाखड़ा-नांगल बांध और हीराकुंड बांध सहित कई सिंचाई परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गईं।
- योजना परिव्यय का लगभग 44.6 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के पक्ष में गया।
- सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू की गईं
- यह योजना सफल रही और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.6% (लक्ष्य से अधिक) हासिल हुई

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961)

- यह पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित था।
- इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था। परिवहन और संचार के बाद दूसरे स्थान पर
- इस योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए
- यह योजना सफल रही और 4.1% की विकास दर हासिल की गई। बंद अर्थव्यवस्था की धारणा के कारण, इस योजना के दौरान खाद्यान्न और पूंजी की कमी महसूस की गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966)

- तीसरी पंचवर्षीय योजना को 'गाडगिल योजना' कहा जाता है
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना तथा स्व-चालित स्थिति तक पहुंचना या उड़ान भरना था।
- योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में 30% और कृषि उत्पादन में 30% की वृद्धि करना था
- भारत-चीन युद्ध के कारण यह योजना 5.6% की विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी

योजना अवकाश या तीन वार्षिक (1966-1969)

- योजना अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत-पाकिस्तान युद्ध और तीसरी योजना की विफलता थी।
- इस अवधि के दौरान वार्षिक योजनाएं (1966-1967, 1967-1968 और 1968-1969) बनाई गईं और कृषि, इसके संबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974)

- इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं अर्थात स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि
- चौदह प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया
- यह योजना असफल रही और 5.7% के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की विकास दर ही हासिल की जा सकी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979)

- इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, उसके बाद उद्योग और खनन को प्राथमिकता दी गई।
- योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया
- बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी) भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
- कुल मिलाकर यह योजना सफल रही, जिससे 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की विकास दर हासिल हुई।
- इस योजना का मसौदा डी.पी. धर ने तैयार किया था और इसे शुरू किया था। इस योजना को 1978 में जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया था।

रोलिंग योजना

- जनता सरकार ने 1977-78 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978-83 की अवधि के लिए अपनी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की।
- 1980 में, केंद्र में पुनः सरकार बदल गई और कांग्रेस की वापसी हुई, जिसने 1980 में ही जनता सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना को त्याग दिया।
- नई सरकार ने 1980-85 की अवधि के लिए एक नई छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की।

- इस योजना (1978-1980) को रोलिंग योजना कहा जाता है

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985)

- इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता था
- यह योजना (1980-85) 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ शुरू की गई थी
- योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया और ग्रामीण गरीबी और क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया
- इसका विकास लक्ष्य 5.2% था लेकिन यह 5.7% ही हासिल कर सका।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990)

- योजना (1985-90) में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार सृजन और सामान्य रूप से उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) 1989 में ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- योजना में विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर भी ध्यान केंद्रित किया गया
- इसका विकास लक्ष्य 5.0% था लेकिन यह 6.0% हासिल कर सका।

दो वार्षिक योजनाएँ

- केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो सकी। इसलिए 1990-91 और 1991-92 में दो वार्षिक कार्यक्रम बनाए गए।
- दो लगातार वार्षिक योजनाएं (1990-92) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के दृष्टिकोण के ढांचे के भीतर तैयार की गईं, जिसमें रोजगार को अधिकतम करने और सामाजिक परिवर्तन पर मुख्य जोर दिया गया

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997)

- इस योजना में मानव संसाधन अर्थात रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
- इस योजना के दौरान, भारत की नई आर्थिक नीति पेश की गई थी।
- आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) को आम तौर पर नए आर्थिक माहौल में शुरू किया गया था
- यह योजना सफल रही और 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

- इस योजना का मुख्य फोकस "न्याय और समानता के साथ विकास" था।

- इस पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई
- सभी के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना
- योजना में सात न्यूनतम सेवाओं पर जोर दिया गया है जिनमें सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता शामिल हैं।
- यह योजना 7% की विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही और भारतीय अर्थव्यवस्था केवल 5.6% की दर से बढ़ी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)

- इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है।
- इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य (2002-07) की अवधि के लिए 8 प्रतिशत औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करना है
- 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतर में कम से कम 50% की कमी लाना
- इसका लक्ष्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना था।
- सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि) पर अधिक जोर
- इसका विकास लक्ष्य 8.0% था लेकिन यह केवल 7.2% ही हासिल कर सका।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

- योजना का लक्ष्य 10 प्रतिशत की विकास दर है तथा इसमें 'तेज और अधिक समावेशी विकास' के विचार पर जोर दिया गया है।
- **सी.रंगराजन** द्वारा तैयार
- इसका विकास दर लक्ष्य 8.1% था लेकिन यह केवल 7.9% ही हासिल कर सका

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)

- इसका मुख्य विषय "तेज़, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास" है।
- सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराना
- सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना
- 90 प्रतिशत भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना
- इसका विकास दर लक्ष्य 8% है।

नीति आयोग

- नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक-टैंक है।

- नीति आयोग भारत में योजना आयोग का स्थान लेने वाला नया योजना निकाय है।
- नीति आयोग एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करता है।
- प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे। उपाध्यक्ष नीति आयोग का कार्यात्मक प्रमुख होता है

नीति आयोग की संरचना

1. अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री (पदेन)।
2. गवर्निंग काउंसिल: इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
3. उपाध्यक्ष-प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा (प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनंगरिया थे)।
4. सदस्य: सभी पूर्णकालिक।
5. अंशकालिक सदस्य: अधिकतम 2, अग्रणी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से पदेन क्षमता में।
6. पदेन सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी: भारत सरकार के सचिव के पद पर, निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

नीति आयोग के कार्य

- सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद: राज्यों को राष्ट्रीय नीति के निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम बनाना।
- विकेन्द्रीकृत योजना: योजना प्रक्रिया को नीचे से ऊपर की ओर मॉडल में पुनर्गठित करना।
- विजन और परिदृश्य योजना: भारत के भविष्य के लिए मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतिक रूपरेखा तैयार करना।
- आंतरिक परामर्श: यह केंद्र और राज्य सरकारों को नीति और कार्यक्रमों पर आंतरिक परामर्श प्रदान करता है।
- निगरानी और मूल्यांकन: यह नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और प्रभावों का मूल्यांकन करेगा।

भारत में कर संरचना

- कर नागरिकों द्वारा सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। यह सरकार द्वारा करदाता पर कानूनी रूप से लगाया जाता है और किसी भी स्थिति में करदाता सरकार को कर देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

उदाहरण: आयकर, कॉर्पोरेट कर, बिक्री कर

- आधुनिक अर्थशास्त्र कर को आय पुनर्वितरण के एक तरीके के रूप में परिभाषित करता है।

प्रत्यक्ष कर

- प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति की आय और संपत्ति पर लगाया जाता है तथा सीधे सरकार को दिया जाता है।

उदाहरण: आयकर, कॉर्पोरेट कर, आदि।

अप्रत्यक्ष कर

- अप्रत्यक्ष कर उस कर को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने पर लगाया जाता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भुगतान किया जाता है।

उदाहरण: बिक्री कर, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि।

कराधान के तरीके

- अर्थव्यवस्थाओं में कराधान की तीन विधियाँ प्रचलित हैं, जिनके अपने-अपने गुण हैं।

1. **प्रतिगामी कराधान**
2. **आनुपातिक कराधान**
3. **प्रगतिशील कराधान**

प्रगतिशील कराधान

- प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जो उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों पर कम कर दर लगाता है, जो इसे करदाता की भुगतान करने की क्षमता पर आधारित बनाता है। इसका मतलब है कि यह कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से अधिक प्रतिशत लेता है।

- भारतीय आयकर प्रगतिशील कर का एक विशिष्ट उदाहरण है। यहाँ विचार यह है कि जो लोग कम कमाते हैं उन पर कम कर लगाया जाए और जो लोग अधिक कमाते हैं उन पर अधिक कर लगाया जाए

- यह दुनिया में सबसे लोकप्रिय कराधान पद्धति है और एक लोकलुभावन भी है

प्रतिगामी कराधान

- प्रतिगामी कर एक ऐसा कर है जो समान रूप से लगाया जाता है, जिसमें उच्च आय वालों की तुलना में कम आय वालों से आय का एक बड़ा प्रतिशत लिया जाता है। यह प्रगतिशील कर के विपरीत है

- इस पद्धति की जहां उच्च उत्पादकों या आय अर्जित करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए सराहना की जाती है, वहीं इसकी आलोचना इस कारण की जाती है कि इससे गरीबों और कम उत्पादकों पर अधिक कर लगता है।

आनुपातिक कराधान

- आनुपातिक कर प्रणाली, जिसे फ्लैट टैक्स प्रणाली भी कहा जाता है, आय या संपत्ति की परवाह किए बिना सभी पर समान कर दर लगाती है।

- बिक्री कर आनुपातिक कर का सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि सभी उपभोक्ता, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, एक ही निश्चित दर पर कर का भुगतान करते हैं

भारत में कराधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि "कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर न तो लगाया जाएगा और न ही वसूला जाएगा"। इसलिए, वसूले जाने वाले हर कर के साथ एक कानून का होना ज़रूरी है।

- भारत में कराधान प्रणाली ऐसी है कि कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं। कुछ छोटे कर स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर पालिका और स्थानीय सरकारों द्वारा भी लगाए और एकत्र किए जाते हैं।

- **प्रमुख केंद्रीय कर**

1. आयकर
2. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)
3. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)
4. सीमा शुल्क
5. कॉर्पोरेट कर
6. उपहार कर

- प्रमुख राज्य कर

1. राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी)
2. स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण
3. व्यावसायिक कर

- **स्थानीय निकाय कर**

1. संपत्ति कर
2. जल कर

- **भारत में कर संरचना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में विभाजित है**

प्रत्यक्ष कर

- प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति की आय और संपत्ति पर लगाया जाता है तथा सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है; ऐसे कर का भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

- यह कर प्रगतिशील प्रकृति का है। इसे व्यक्ति की भुगतान क्षमता के अनुसार लगाया जाता है, अर्थात कर अमीरों से अधिक और गरीबों से कम वसूला जाता है

- प्रत्यक्ष करों की योजनाओं और नीतियों की सिफारिश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा की जा रही है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है।
- उदाहरण: आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और उपहार कर

प्रत्यक्ष करों के लाभ

- प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं यानी कर की दर कर आधार के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, आयकर समानता के सिद्धांत को पूरा करता है।
- प्रत्यक्ष करों के संग्रह की लागत अपेक्षाकृत कम है। करदाता सीधे राज्य को कर का भुगतान करते हैं।
- प्रत्यक्ष कर भी लोच के सिद्धांत को पूरा करते हैं। आयकर प्रकृति में आय लोचदार है। जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता है, सरकार को मिलने वाला कर राजस्व भी अपने आप बढ़ जाता है
- प्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है।

प्रत्यक्ष करों के दोष

- प्रत्यक्ष कर उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नागरिक अधिक आय अर्जित करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उस स्थिति में उन्हें अधिक कर चुकाना होगा।
- प्रत्यक्ष कर का बोझ इतना भारी होता है कि करदाता हमेशा कर चोरी करने की कोशिश करते हैं। इससे काला धन पैदा होता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है

अप्रत्यक्ष कर

- अप्रत्यक्ष कर को उस व्यक्ति पर लगाया जाने वाला कर कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और इसका भुगतान अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को किया जाता है। कर का बोझ आसानी से दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है। यह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लगाया जाता है, चाहे वे अमीर हों या गरीब। उदाहरण: जीएसटी, सीमा शुल्क, आदि।

अप्रत्यक्ष करों के लाभ

- सभी उपभोक्ताओं को, चाहे वे अमीर हों या गरीब, अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है। इस कारण से, यह कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक लोगों को कवर कर सकते हैं।
- सरकार उन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं जैसे तंबाकू, शराब आदि। इन्हें पाप कर के रूप में जाना जाता है।

अप्रत्यक्ष करों के दोष

- अप्रत्यक्ष कर कभी-कभी अन्यायपूर्ण और प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों व्यक्तियों को अपने आय स्तर के बावजूद कर के रूप में समान राशि का भुगतान करना पड़ता है।
- अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों की तुलना में कम लचीले होते हैं। चूंकि अप्रत्यक्ष कर आम तौर पर आनुपातिक होते हैं।

जीएसटी (माल और सेवा कर)

- जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है

- जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है।
- वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसका आदर्श वाक्य एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर है।
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है।
- जीएसटी देश में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।

गंतव्य आधारित

- जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है

उदाहरण: तेलंगाना में निर्मित वस्तुओं पर विचार करें और उन्हें कर्नाटक में अंतिम उपभोक्ता को बेचा जाता है। चूंकि वस्तु एवं सेवा कर उपभोग के बिंदु पर लगाया जाता है, इस मामले में, कर्नाटक, इसलिए पूरा कर राजस्व कर्नाटक को जाएगा, न कि तेलंगाना को।

जीएसटी के घटक

- जीएसटी के घटक जीएसटी के घटक तीन प्रकार के हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी।

1. सीजीएसटी: केंद्र सरकार द्वारा अंतर-राज्यीय बिक्री पर एकत्रित किया गया (उदाहरण: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर)

2. एसजीएसटी: राज्य सरकार द्वारा अंतर-राज्यीय बिक्री पर एकत्रित किया गया (उदाहरण: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर)

3. आईजीएसटी: अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित (उदाहरण: महाराष्ट्र से कर्नाटक)

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर संरचना निम्नानुसार होगी

लेन-देन	नया प्रशासन	पुरानी व्यवस्था	टिप्पणी
माल या सेवाएं (राज्य के भीतर बिक्री)	सीजीएसटी + एसजीएसटी	वैट + केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर	1. राजस्व को दोनों पक्षों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा केंद्र और राज्य
माल या सेवाएं (दूसरे राज्य को बिक्री)	आईजीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर + उत्पाद शुल्क/सेवा कर	1. आईजीएसटी कर तब लगाया जाता है जब वस्तुओं और सेवाओं का अंतर-राज्यीय

			हस्तांतरण होता है। 2. केंद्र सरकार आईजीएसटी राजस्व को उसके आधार पर साझा करेगी। माल का गंतव्य

अन्य महत्वपूर्ण विवरण

- जीएसटी निम्नलिखित के अलावा सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू है:

1. मानव उपभोग के लिए मादक शराब
2. पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन)।

- निर्माता/आपूर्तिकर्ता से लेकर उपभोक्ता तक कई तरह के करों की जगह एकल कर। जीएसटी में राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। जीएसटी से पहले की व्यवस्था में अप्रत्यक्ष करों की सूची इस प्रकार है:

1. राज्य वैट/बिक्री कर
2. केंद्रीय बिक्री कर
3. क्रय कर
4. विलासिता कर
5. मनोरंजन और आमोद-प्रमोद कर
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7. सेवा कर
8. अतिरिक्त सीमा शुल्क
9. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
10. विज्ञापनों पर कर
11. लॉटरी, सट्टेबाज़ी और जुए पर कर

भारत में वर्तमान जीएसटी दरें

- वर्तमान में, भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दर को 7 स्लैब में विभाजित किया गया है; ये हैं 0% (शून्य) जीएसटी, 0.25% जीएसटी, 3% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी और 28% जीएसटी

जीएसटी के लाभ

1. कैस्केडिंग कर प्रभाव को हटाना
2. एकल बिंदु कर
3. असंगठित क्षेत्र का विनियमन
4. जीएसटी के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया सरल
5. लॉजिस्टिक्स में दक्षता में वृद्धि

भारत में सार्वजनिक वित्त

- सार्वजनिक वित्त सरकार के वित्तीय पहलुओं का अध्ययन है। यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय से संबंधित है
- सार्वजनिक वित्त का उल्लेख कौटिल्य के प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है जिसमें 'राजकोष, राजस्व के स्रोत, खाते और लेखा परीक्षा' को बहुत विस्तृत तरीके से शामिल किया गया है।

बजट

- बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय और व्यय को दर्शाता है।
- भारत एक संघीय अर्थव्यवस्था है; इसलिए सार्वजनिक बजट सरकार के दो स्तरों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार को अनुच्छेद 112 के तहत संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी केंद्रीय बजट प्रस्तुत करना होता है और प्रत्येक राज्य सरकार को अनुच्छेद 202 के तहत विधानसभा में राज्य के लिए इसे प्रस्तुत करना होता है।

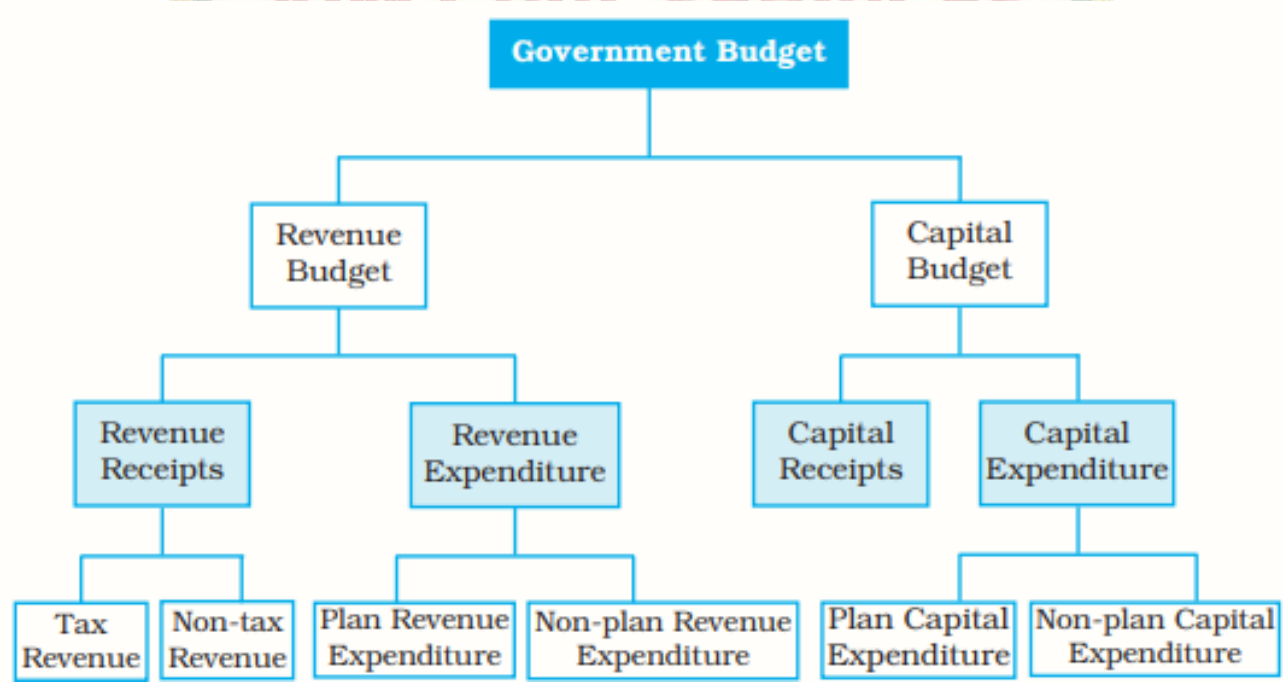

- राजस्व खाते और अन्य खातों पर व्यय के आधार पर बजट दो तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है:

o राजस्व बजट: इसमें राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व व्यय को योजना राजस्व व्यय और गैर-योजना राजस्व व्यय में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

o पूंजी बजट: इसमें पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय शामिल होते हैं। इस मामले में, पूंजी प्राप्तियों के मुख्य स्रोत ऋण, अग्रिम आदि हैं। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय को योजना पूंजीगत व्यय और गैर-योजना पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है।

राजस्व प्राप्तियां

- राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो सरकार पर दावा नहीं करती हैं। इसलिए उन्हें गैर-प्रतिदेय कहा जाता है। उन्हें कर और गैर-कर राजस्व में विभाजित किया जाता है

- कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण घटक है। करों के प्रकार हैं

1. प्रत्यक्ष कर - व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, आदि।

2. अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क (भारत में आयातित और भारत से बाहर निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए कर), जीएसटी, आदि।

- सरकार के गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर लाभांश और लाभ, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। विदेशी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नकद अनुदान सहायता भी इसमें शामिल है।

राजस्व व्यय

- राजस्व व्यय वह व्यय है जो सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पक्षों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए व्यय से संबंधित है।

- बजट दस्तावेज कुल व्यय को योजनागत और गैर-योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं

- केंद्रीय योजनाओं (पंचवर्षीय योजनाओं) से संबंधित योजना राजस्व व्यय तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता।

- गैर-योजना राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का अधिक महत्वपूर्ण घटक है, जो सरकार की सामान्य, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। गैर-योजना व्यय की मुख्य मदें ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएँ, सब्सिडी, वेतन और पेंशन हैं।

पूंजी प्राप्तियां

- सरकार की सभी गैर-राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं।

- सरकार को ऋण के माध्यम से या अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री से धन प्राप्त होता है। ऋण उन एजेंसियों को वापस करना होगा जिनसे उन्हें उधार लिया गया है। इस प्रकार वे देयता बनाते हैं। सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में शेयरों की बिक्री जिसे पीएसयू विनिवेश के रूप में जाना जाता है, सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की कुल राशि को कम करती है। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता बनाती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, उन्हें पूंजी प्राप्तियां (भविष्य निधि (पीएफ), डाक जमा, विभिन्न लघु बचत योजनाएं और जनता को बेचे जाने वाले सरकारी बांड) कहा जाता है।

पूंजीगत व्यय

- सरकार के कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। इसमें भूमि, भवन, मशीनरी और उपकरणों के अधिग्रहण, शेयरों में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर व्यय शामिल हैं।

- बजट दस्तावेजों में पूंजीगत व्यय को भी योजना और गैर-योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है

- योजनागत पूंजीगत व्यय, अपने राजस्व समकक्ष की तरह, केंद्रीय योजना तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से संबंधित है।

- गैर-योजना पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं।

संतुलित, अधिशेष और घाटे का बजट संतुलित बजट

- सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है। इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। सरकार का अनुमानित राजस्व = सरकार का प्रस्तावित व्यय।

अधिशेष बजट

- बजट अधिशेष बजट होता है जब वर्ष का अनुमानित राजस्व प्रत्याशित व्यय से अधिक होता है।

सरकार अनुमानित राजस्व > अनुमानित सरकारी व्यय घाटा बजट

- घाटे का बजट वह होता है जिसमें अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित राजस्व से अधिक होता है।

सरकार का अनुमानित राजस्व < सरकार का प्रस्तावित व्यय।

बजटीय घाटा

- जब सरकार राजस्व से अधिक खर्च करती है, तो उसे बजट घाटा होता है

- भारतीय सरकार के बजट के संदर्भ में, बजट घाटा चार प्रमुख प्रकार का होता है।

1. **राजस्व घाटा**
2. **बजट घाटा**
3. **राजकोषीय घाटा**
4. **प्राथमिक घाटा**

राजस्व घाटा

- राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियां

घाटा बजट

- बजट घाटा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय (राजस्व और पूंजी दोनों) के बीच का अंतर है

बजट घाटा = कुल व्यय – कुल राजस्व

प्राथमिक घाटा

- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने के बराबर होता है।
- यह सरकार के वास्तविक बोझ को दर्शाता है और इसमें पूर्व में लिए गए ऋणों पर ब्याज का बोझ शामिल नहीं है।

प्राथमिक घाटा (पीडी) = राजकोषीय घाटा (पीडी) - ब्याज भुगतान (आईपी)

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है

राजकोषीय नीति

- राजकोषीय नीति को 'सरकारी खरीद के स्तर, स्थानान्तरण के स्तर और कर संरचना के संबंध में सरकार की नीति' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- राजकोषीय नीति को 'सरकारी व्यय और करों में परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो व्यापक आर्थिक नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं'
- मैक्रो-इकोनॉमिक पॉलिसी के एक साधन के रूप में, राजकोषीय नीति आधुनिक सरकारों के बीच बहुत लोकप्रिय रही है। राजकोषीय नीति का बढ़ता महत्व महामंदी और कीन्स द्वारा 'न्यू इकोनॉमिक्स' के विकास के कारण था।

AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE BUREAUCRATS
WITH IGNITED MINDS

राजकोषीय साधन

- राजकोषीय नीति को राजकोषीय साधनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिन्हें 'राजकोषीय उपकरण' या राजकोषीय लीवर भी कहा जाता है: सरकारी व्यय, कराधान और उधार राजकोषीय उपकरण हैं।

1. **कराधान** : कर लोगों से सरकार को आय हस्तांतरित करते हैं। कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होते हैं। कर में वृद्धि से प्रयोज्य आय कम हो जाती है। इसलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कराधान बढ़ाया जाना चाहिए। मंदी के दौरान, करों को कम किया जाना चाहिए।

2. **सार्वजनिक व्यय** : सार्वजनिक व्यय कर्मचारियों के वेतन और मज़दूरी बढ़ाता है और इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को बढ़ाता है। इसलिए मंदी से लड़ने के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए घटाया जाता है।

3. सार्वजनिक ऋण : जब सरकार ऋण जारी करके उधार लेती है, तो जनता से सरकार को धन हस्तांतरित होता है। ब्याज भुगतान और सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के समय, सरकार से जनता को धन हस्तांतरित होता है।

राजकोषीय नीति के उद्देश्य

1. पूर्ण रोजगार
2. मूल्य स्थिरता
3. आर्थिक विकास
4. न्यायसंगत वितरण
5. बाहरी स्थिरता
6. पूंजी निर्माण
7. क्षेत्रीय संतुलन

वित्त आयोग

- वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में केंद्र और राज्य के बीच राजकोषीय संबंधों की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए की गई थी।
- संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग हर पांच साल में केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करता है।
- वित्त आयोग का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच राजकोषीय असंतुलन को कम करना है। यह समावेशिता को बढ़ावा देता है।
- वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसका गठन सामान्यतः अवधि से दो वर्ष पहले किया जाता है।
- 15वें वित्त आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में की गई है।
- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष - एनके सिंह

भारत में बाह्य क्षेत्र

- किसी अर्थव्यवस्था की सभी आर्थिक गतिविधियाँ जो विदेशी मुद्रा में होती हैं, बाह्य क्षेत्र में आती हैं जैसे निर्यात, आयात, विदेशी निवेश, बाह्य ऋण, भुगतान संतुलन, चालू खाता, पूंजी खाता, आदि।

व्यापार

- व्यापार आर्थिक एकीकरण की शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। 'व्यापार' शब्द का अर्थ है लोगों के बीच वस्तुओं, माल या माल का आदान-प्रदान।

भुगतान संतुलन

- भुगतान संतुलन (बीओपी) एक निश्चित समय अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) के लिए किसी देश के निवासियों के बीच बाकी दुनिया के साथ वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों में लेन-देन को रिकॉर्ड करता है। मूल रूप से, यह किसी अर्थव्यवस्था के चालू और पूंजी खातों का शुद्ध परिणाम है
- भुगतान संतुलन (बीओपी) में दो मुख्य खाते हैं - चालू खाता और पूंजी खाता।

चालू खाता

- चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और हस्तांतरण भुगतान का रिकॉर्ड है।
- इसमें वस्तुओं और सेवाओं के सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन, अंतर्राष्ट्रीय सेवा लेनदेन (अर्थात पर्यटन, परिवहन और रॉयल्टी शुल्क) और अंतर्राष्ट्रीय एकतरफा हस्तांतरण (अर्थात उपहार और विदेशी सहायता) शामिल हैं।

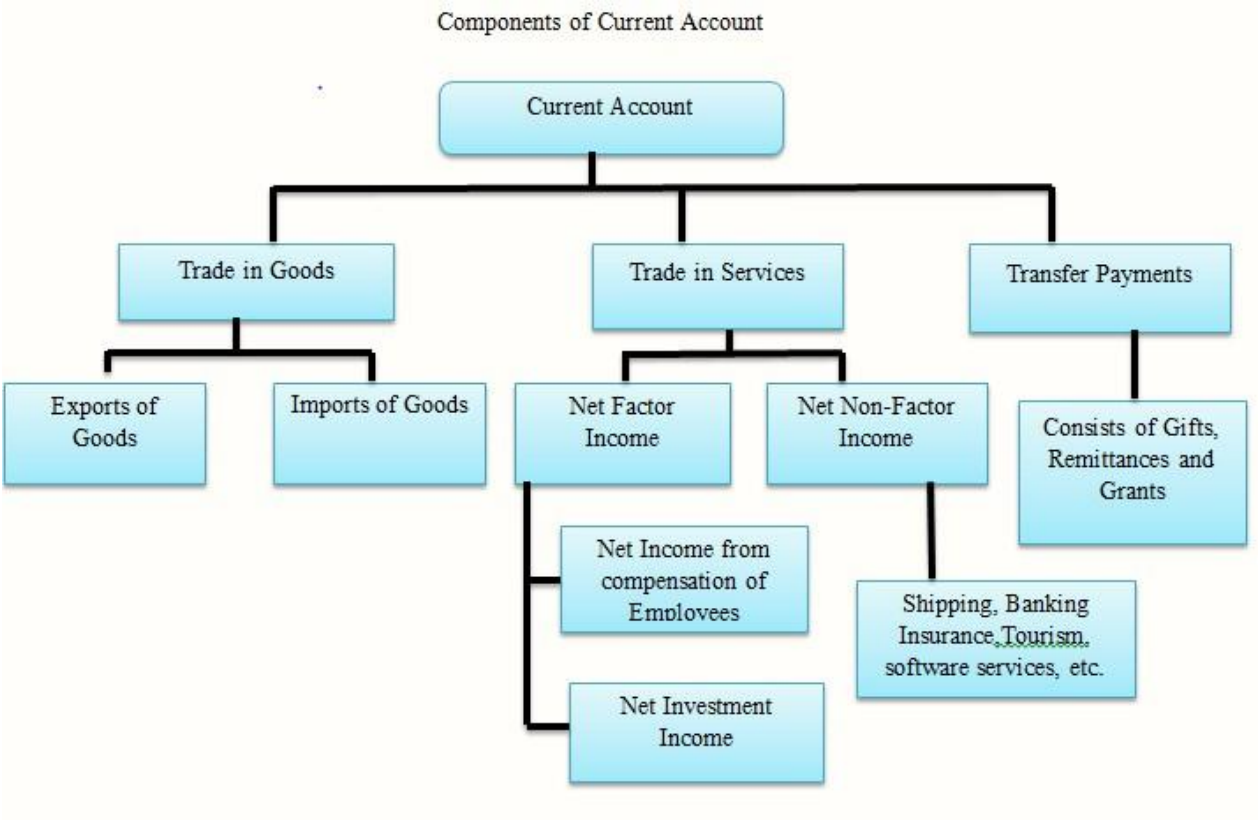

- वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात और आयात शामिल है
- सेवाओं के व्यापार में कारक आय और गैर-कारक आय लेनदेन शामिल हैं
- हस्तांतरण भुगतान वे रसीदें हैं जो किसी देश के निवासियों को 'मुफ़्त' में मिलती हैं, बदले में उन्हें कोई सामान या सेवा प्रदान नहीं करनी होती। इनमें उपहार, प्रेषण और अनुदान शामिल हैं। ये सरकार या विदेश में रहने वाले निजी नागरिकों द्वारा दिए जा सकते हैं।

चालू खाते पर शेष राशि

- चालू खाता तब शेष होता है जब चालू खाते पर प्राप्तियां चालू खाते पर भुगतान के बराबर होती हैं।

1. **प्राप्तियां = भुगतान (संतुलित चालू खाता)**

• अधिशेष चालू खाता का अर्थ है कि राष्ट्र अन्य देशों को ऋणदाता है और घाटे वाले चालू खाता का अर्थ है कि राष्ट्र अन्य देशों से ऋण लेता है।

1. **प्राप्तियां > भुगतान (चालू खाता अधिशेष)**
2. **प्राप्तियां < भुगतान (चालू खाता घाटा)**

• **चालू खाते के शेष के दो घटक हैं:**

1. व्यापार संतुलन या व्यापार संतुलन
2. अदृश्य पर संतुलन

व्यापार संतुलन (बीओटी)

• यह किसी निश्चित समयावधि में किसी देश के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच का अंतर है।

• माल के निर्यात को व्यापार संतुलन (बीओटी) में क्रेडिट मद के रूप में दर्ज किया जाता है, जबकि माल के आयात को व्यापार संतुलन (बीओटी) में डेबिट मद के रूप में दर्ज किया जाता है। इसे व्यापार संतुलन के रूप में भी जाना जाता है।

• व्यापार संतुलन (बीओटी) तब संतुलन में कहा जाता है जब वस्तुओं का निर्यात वस्तुओं के आयात के बराबर होता है। अधिशेष बीओटी या व्यापार अधिशेष तब पैदा होगा जब देश आयात की तुलना में अधिक वस्तुओं का निर्यात करता है। जबकि, घाटा बीओटी या व्यापार घाटा तब पैदा होगा जब कोई देश निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं का आयात करता है।

अदृश्य पर संतुलन

• शुद्ध अदृश्य एक निश्चित समयावधि में किसी देश के निर्यात मूल्य और अदृश्य आयात मूल्य के बीच का अंतर है।

• अदृश्य में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाएँ, स्थानान्तरण और आय का प्रवाह शामिल हैं।

• सेवा व्यापार में कारक और गैर-कारक आय दोनों शामिल हैं। कारक आय में उत्पादन के कारकों (जैसे भूमि, श्रम और पूंजी) पर शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आय शामिल है। गैर-कारक आय शिपिंग, बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाओं आदि जैसे सेवा उत्पादों की शुद्ध बिक्री है।

पूंजी खाता

• प्रत्यक्ष निवेश और ब्याज-असर वाले वित्तीय साधनों, गैर-ब्याज वाले मांग जमा और सोने की खरीद से जुड़े वित्तीय लेनदेन पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं

• पूंजी खाता परिसंपत्तियों के सभी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। परिसंपत्ति किसी भी रूप में धन धारण किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, धन, स्टॉक, बांड, सरकारी ऋण, आदि।

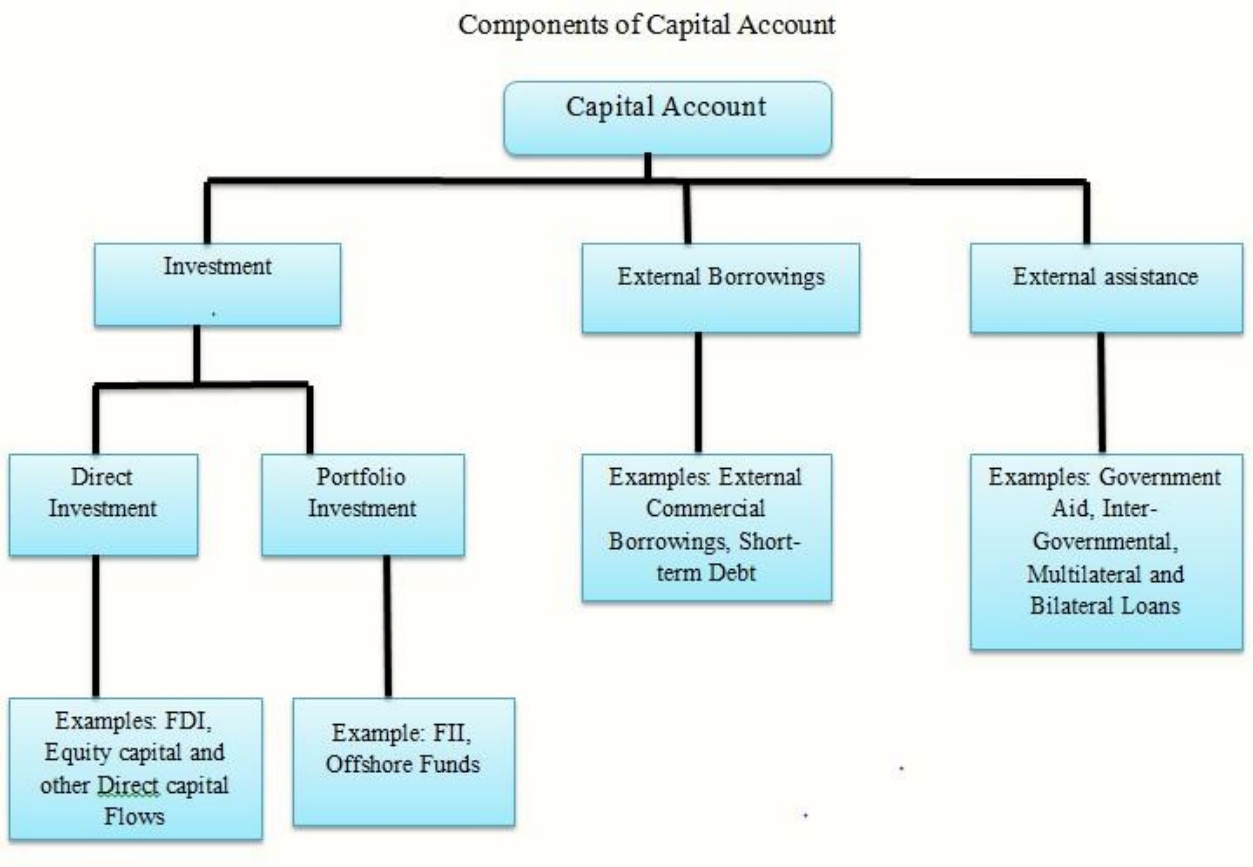

पूंजी खाते पर शेष राशि

- पूंजी खाता तब संतुलित होता है जब पूंजी अंतर्वाह (जैसे विदेश से ऋण प्राप्त करना, विदेशी कंपनियों में परिसंपत्तियों या शेयरों की बिक्री) पूंजी बहिर्वाह (जैसे ऋणों का पुनर्भुगतान, विदेशी देशों में परिसंपत्तियों या शेयरों की खरीद) के बराबर होता है।

- पूंजी खाते में अधिशेष तब उत्पन्न होता है जब पूंजी प्रवाह पूंजी बहिर्वाह से अधिक होता है, जबकि पूंजी खाते में घाटा तब उत्पन्न होता है जब पूंजी प्रवाह पूंजी बहिर्वाह से कम होता है।

भुगतान संतुलन असंतुलन

- भुगतान संतुलन तब कहा जाता है जब प्राप्तियां (आर) और भुगतान (पी) बराबर हों

आर / पी = 1

- अनुकूल BoP: जब प्राप्तियां भुगतान से अधिक होती हैं, तो BoP को अनुकूल कहा जाता है।

आर / पी > 1

प्रतिकूल बीओपी: जब प्राप्तियां भुगतान से कम होती हैं, तो बीओपी को प्रतिकूल या प्रतिकूल कहा जाता है।

आर / पी < 1

विनिमय दर

विदेशी मुद्रा की परिभाषा

- विदेशी मुद्रा एक राष्ट्रीय मुद्रा को दूसरे में परिवर्तित करने तथा एक देश से दूसरे देश में धन स्थानांतरित करने की प्रणाली या प्रक्रिया है।

विदेशी मुद्रा भंडार

- किसी अर्थव्यवस्था के पास एक समय पर मौजूद कुल विदेशी मुद्राएं (विभिन्न देशों की) उसकी 'विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां/भंडार' होती हैं।

- किसी अर्थव्यवस्था का विदेशी मुद्रा भंडार उसकी 'विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां' होती हैं, जिसमें उसके स्वर्ण भंडार, एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) और आईएमएफ में रिजर्व ट्रैन्च स्थिति (आरटीपी) को जोड़ा जाता है।

विदेशी मुद्रा बाजार

- वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे के लिए कारोबार होता है, विदेशी मुद्रा बाजार के रूप में जाना जाता है।

- विदेशी मुद्रा बाजार में प्रमुख प्रतिभागी वाणिज्यिक बैंक, विदेशी मुद्रा दलाल और अन्य अधिकृत डीलर और मौद्रिक प्राधिकरण हैं।

विनिमय दर

- एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत को विदेशी विनिमय दर या केवल विनिमय दर के रूप में जाना जाता है।

- विनिमय बाजार में लेन-देन विनिमय दरों पर किए जाते हैं। यह घरेलू मुद्रा का बाहरी मूल्य है। इस प्रकार, विनिमय दर को विदेशी मुद्रा की एक इकाई (मान लीजिए 1 अमेरिकी डॉलर) के लिए घरेलू मुद्रा (मान लीजिए ₹ 72) में भुगतान की गई कीमत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

विनिमय दर प्रणालियों के प्रकार

- दो प्रमुख विनिमय दर प्रणालियाँ हैं, अर्थात्,

(1) निश्चित (या आंकी गई) विनिमय दर प्रणाली और

(2) लचीली (या अस्थिर) विनिमय दर प्रणाली।

- कुछ देशों में प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली भी प्रचलित है (उदाहरण: भारत)

निश्चित विनिमय दरें

- निश्चित विनिमय दर (जिसे स्थिर विनिमय दर और पेग्ड विनिमय दर के रूप में भी जाना जाता है) प्रणाली का पालन करने वाले देश अपनी मुद्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित एक निश्चित दर पर रखने के लिए सहमत होते हैं। स्वर्ण मानक के तहत, मुद्राओं का मूल्य सोने के संदर्भ में तय किया गया था।

लचीली विनिमय दरें

- लचीली विनिमय दर (जिसे फ्लोटिंग विनिमय दर भी कहा जाता है) प्रणाली के तहत, विनिमय दरें खुले बाजार में मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती हैं

विनिमय दर के निर्धारक

1. मुद्रास्फीति में अंतर

- मुद्रास्फीति और विनिमय दरें विपरीत रूप से संबंधित हैं। लगातार कम मुद्रास्फीति दर वाले देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, क्योंकि अन्य मुद्राओं के सापेक्ष उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है

2. सार्वजनिक ऋण

- बड़े सार्वजनिक ऋण विदेशी निवेशकों को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति बढ़ रही है। नतीजतन, विनिमय दर कम होगी।

3. चालू खाता घाटा

- चालू खाते में घाटा प्राप्तियों की तुलना में भुगतान की अधिकता को दर्शाता है। देश घाटे की भरपाई के लिए विदेशी स्रोतों से पूंजी उधार लेता है। विदेशी मुद्रा की अत्यधिक मांग देश की विनिमय दर को कम करती है

4. मंदी

- मंदी के दौर में ब्याज दरें कम होती हैं। इससे विदेशी पूंजी का प्रवाह कम हो जाएगा। नतीजतन, एक मुद्रा का अन्य मुद्राओं के मुकाबले अवमूल्यन होगा, जिससे विनिमय दर कम हो जाएगी।

प्रशंसा

- मूल्यवृद्धि का अर्थ है किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य विदेशी मुद्रा के मुकाबले वृद्धि।
- मूल्यवृद्धि से निर्यात महंगा हो जाता है और आयात सस्ता हो जाता है।

मूल्यह्रास

- विदेशी मुद्रा बाजार में, यह एक ऐसी स्थिति है जब घरेलू मुद्रा बाजार संचालित होने पर विदेशी मुद्रा के सामने अपना मूल्य खो देती है।
- इसका अर्थ है कि किसी मुद्रा में अवमूल्यन तभी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था अस्थिर विनिमय दर प्रणाली का अनुसरण करती है।

अवमूल्यन

- विदेशी मुद्रा बाजार में जब किसी घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को उसकी सरकार द्वारा किसी विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम कर दिया जाता है, तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। इसका मतलब है कि आधिकारिक मूल्यह्रास ही अवमूल्यन है।

पुनर्मूल्यांकन

- विदेशी मुद्रा बाजार में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द जिसका मतलब है कि सरकार किसी विदेशी मुद्रा के मुकाबले अपनी मुद्रा की विनिमय दर बढ़ा रही है। इसे आधिकारिक प्रशंसा कहते हैं।

AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE BUREAUCRATS
WITH IGNITED MINDS

महत्वपूर्ण शर्तें

सॉफ्ट करेंसी

- विदेशी मुद्रा बाजार में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द जो किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध मुद्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, रुपया भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में एक नरम मुद्रा है।

कठिन मुद्रा

- हार्ड करेंसी, सुरक्षित मुद्रा या मजबूत मुद्रा कोई भी वैश्विक रूप से कारोबार की जाने वाली मुद्रा है जो मूल्य के विश्वसनीय और स्थिर भंडार के रूप में कार्य करती है।
- दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा वह है जिसमें तरलता का स्तर उच्च हो।
- आज दुनिया की कुछ सर्वोत्तम कठोर मुद्राएं अमेरिकी डॉलर, यूरो (€), जापानी येन (¥) और यूके स्टर्लिंग पाउंड (£) हैं।

सस्ती मुद्रा

- इस शब्द का पहली बार प्रयोग अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स (1930 के दशक) द्वारा किया गया था।
- यदि कोई सरकार अपने बांडों को उनकी परिपक्वता से पहले (पूर्ण परिपक्वता मूल्य पर) पुनः खरीदना शुरू कर देती है, तो अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होने वाले धन को सस्ती मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जिसे सस्ता धन भी कहा जाता है।
- बैंकिंग उद्योग में, इसका अर्थ तुलनात्मक रूप से कम/नरम ब्याज दर व्यवस्था की अवधि है

गर्म मुद्रा

- हॉट करेंसी फॉरेक्स बाजार का एक शब्द है और यह किसी भी हार्ड करेंसी के लिए एक अस्थायी नाम है
- जब कोई हार्ड करेंसी किसी अर्थव्यवस्था से तीव्र गति से बाहर निकल रही हो, उस समय उस हार्ड करेंसी को हॉट करेंसी कहा जाता है

गरम मुद्रा

- विदेशी मुद्रा बाजार में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द घरेलू मुद्रा को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने की उच्च प्रवृत्ति के कारण मूल्यह्रास के दबाव में है। इसे मुद्रा के तहत गर्मी या हैमरिंग के रूप में भी जाना जाता है।

प्रिय मुद्रा

- जब सरकार बांड जारी करती है, तो जनता से सरकार की ओर या सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में जो धन प्रवाहित होता है, उसे प्रिय मुद्रा कहा जाता है, जिसे प्रिय धन भी कहा जाता है।
- बैंकिंग उद्योग में, इसका अर्थ तुलनात्मक रूप से उच्च/महंगी ब्याज दर व्यवस्था की अवधि है

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में एफडीआई एक महत्वपूर्ण कारक है। विदेशी व्यापार और एफडीआई का आपस में गहरा संबंध है।

- एफडीआई का मतलब है किसी विदेशी देश में निवेश जिसमें प्रबंधन में कुछ हद तक नियंत्रण और भागीदारी शामिल है। यह किसी विदेशी देश में किसी बहुराष्ट्रीय उद्यम द्वारा किए गए निवेश के अनुरूप है। यह पोर्टफोलियो निवेश से अलग है, जो मुख्य रूप से अल्पकालिक लाभ से प्रेरित होता है और इसमें प्रबंधन नियंत्रण की मांग नहीं की जाती है।

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का अर्थ है किसी देश में धन का प्रवेश, जहां विदेशी लोग देश के बैंक में पैसा जमा करते हैं या स्टॉक और बॉन्ड बाजारों में खरीदारी करते हैं, कभी-कभी सट्टेबाजी के लिए। एफपीआई बीओपी के पूंजी खाते का हिस्सा है।

- विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) हेज फंड, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड में किया जाने वाला निवेश है। भारत के वित्तीय क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेश एक आम शब्द है

भारत में एफडीआई

- भारत में एफडीआई पूंजी के मुक्त प्रवाह, उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रबंधन विशेषज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के संदर्भ में लाभप्रद रहा है।

- भारत में एफडीआई की अनुमति स्वचालित मार्ग के तहत है। इसके लिए भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

- भारत में एफडीआई से लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं वित्तीय क्षेत्र (बैंकिंग और गैर-बैंकिंग), बीमा, दूरसंचार, आतिथ्य और पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी।

- निम्नलिखित क्षेत्र एफडीआई के लिए प्रतिबंधित हैं

1. लॉटरी व्यवसाय
2. जुआ और सट्टा
3. चिटफंड का कारोबार
4. निधि कंपनी
5. हस्तांतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) में व्यापार
6. परमाणु ऊर्जा

भारत में मानव विकास

मानव विकास सूचकांक

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता आ रहा है। मानव विकास सूचकांक ने सरकार को लोगों के जीवन स्तर को वास्तविक रूप से ऊपर उठाने में मदद की।

- एचडीआई को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा 1990 में विकसित किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

- एचडीआई का निर्माण जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर किया जाता है

- मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित तीन संकेतकों पर आधारित है

1. दीर्घायु को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है
2. शैक्षिक उपलब्धियां
3. जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है

आयाम सूचकांक = (वास्तविक मूल्य - न्यूनतम मूल्य) / (अधिकतम मूल्य - न्यूनतम मूल्य)

- प्रत्येक आयाम में प्रदर्शन को निम्नलिखित सूत्र लागू करके 0 और 1 के बीच के मान के रूप में व्यक्त किया जाता है ।

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट (2019) के अनुसार, भारत को 189 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। 189 देशों में से भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है

- मानव विकास सूचकांक के शीर्ष तीन देश

1. नॉर्वे (0.954)
2. स्विटजरलैंड (0.946)
3. आयरलैंड (0.942)

- लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) में भारत 162 देशों में 122वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देश चीन (39), श्रीलंका (86), भूटान (99), म्यांमार (106) सूचकांक में भारत से ऊपर हैं।

समावेशी विकास को बढ़ावा देना

- भारतीय विकास योजना का फोकस समाज के 'हाशिए पर पड़े और गरीब वर्गों' को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण पर रहा है।

- अगस्त 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और रुपे कार्ड वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये दोनों योजनाएं एक-दूसरे की पूरक हैं और वित्तीय समावेशन, बीमा पैठ और डिजिटलीकरण जैसे कई उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगी।

- भारत सरकार ने हमेशा रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता में सुधार को प्राथमिकता दी है। देश में 'रोजगार सृजन' के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल

उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना।

अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण शब्द

1. **प्रति व्यक्ति आय** : प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय। यह राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करके प्राप्त की जाती है।

2. **सकल घरेलू उत्पाद** : किसी देश द्वारा किसी विशिष्ट अवधि, सामान्यतः एक वर्ष, में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य

3. **जीएनपी** : किसी विशेष वर्ष (एक वर्ष) के दौरान किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, जिसमें मूल्यह्रास और शुद्ध निर्यात शामिल हैं

4. **एनएनपी** : किसी विशेष वर्ष (एक वर्ष) के दौरान किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, शुद्ध निर्यात सहित मूल्यह्रास को छोड़कर

5. **कारक लागत पर एनएनपी** : उत्पादन के कारकों को किए गए आय भुगतान का कुल योग

6. **व्यक्तिगत आय** : प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पहले किसी देश के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल आय

7. **आर्थिक विकास** : किसी अर्थव्यवस्था का अल्प विकास की स्थिति से विकास की स्थिति में परिवर्तन, जिसे सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है

8. **राष्ट्रीयकरण** : निजी संपत्ति स्वामित्व को सरकारी स्वामित्व में बदलने की प्रक्रिया।

9. **मानव विकास सूचकांक** : यह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आँकड़ा है।

10. **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** : किसी अन्य देश के निवेशक द्वारा किसी व्यवसाय में किया गया निवेश।

11. **एसएलआर** : वैधानिक तरलता अनुपात वह राशि है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले नकदी या सोने या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है

12. **एसईजेड** : यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ाना है

13. **वैश्वीकरण** : वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है।

14. **बेरोजगारी** : जब ऐसे लोग होते हैं जो काम करने के इच्छुक होते हैं और काम करने में सक्षम होते हैं लेकिन उन्हें उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती।

15. **खुली बेरोजगारी** : बेरोजगार व्यक्तियों की पहचान तब की जाती है जब वे बिना काम के रहते हैं

16. **मौसमी बेरोजगारी** : इसमें रोजगार केवल एक विशेष मौसम में ही मिलता है तथा श्रमिक वर्ष की शेष अवधि में बेरोजगार रहते हैं।

17. **पूर्ण रोजगार** : जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक हैं और काम करने में सक्षम हैं, उनके पास रोजगार या नौकरी होनी चाहिए

18. **गरीबी** : वह स्थिति जहाँ लोगों की भोजन, वस्त्र और आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं।

19. **उदारीकरण** : उदारीकरण से तात्पर्य आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में सरकारी प्रतिबंधों में ढील से है।

20. **मूल्य** : विनिमय दर में किसी वस्तु की अन्य वस्तुओं पर नियंत्रण करने की शक्ति

21. **मूल्य** : किसी वस्तु का धन के रूप में व्यक्त मूल्य

22. **उपभोग** : अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग।

23. **समष्टि अर्थशास्त्र** : अर्थशास्त्र की वह शाखा जो किसी अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का समग्र रूप से अध्ययन करती है

24. **व्यष्टि अर्थशास्त्र** : अर्थशास्त्र का वह भाग जो एकल कारकों और व्यक्तिगत निर्णयों के प्रभावों से संबंधित है।

25. **आर्थिक प्रणाली** : वह तरीका जिसमें व्यक्ति और संस्थाएं किसी विशेष क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए एक साथ जुड़ी होती हैं

26. **पूंजीवाद** : वह प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं तथा बाजार आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करता है।

27. **समाजवाद** : समाज को संगठित करने का एक तरीका जिसमें प्रमुख आर्थिक गतिविधियों का स्वामित्व और नियंत्रण व्यक्तिगत लोगों और कंपनियों के बजाय सरकार के पास होता है

28. **मिश्रितवाद** : एक विचारधारा जो अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद (निजी भूमिका) और समाजवाद (राष्ट्रीय भूमिका) के सिद्धांतों को मिश्रित या संयोजित करती है।

29. **धन** : एक परिसंपत्ति जो आम तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य है

30. **मुद्रा की आपूर्ति** : यह किसी भी समय अर्थव्यवस्था में प्रचलन में मौजूद मुद्रा की मात्रा को संदर्भित करता है

31. **मुद्रास्फीति** : कीमतों के औसत स्तर में वृद्धि

32. **अपस्फीति** : कीमतों के औसत स्तर में गिरावट, मुद्रास्फीति के विपरीत

33. **डिस्इन्फ्लेशन** : प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किए बिना मुद्रास्फीति को उलटने की प्रक्रिया।

34. **मुद्रास्फीतिजनित मंदी** : बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की उच्च दर का सह-अस्तित्व।

35. **ऋण सृजन** : इसका अर्थ है ऋण और अग्रिमों का गुणन। वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा प्राप्त करते हैं और इन जमाओं का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं।

36. **बैंक दर** : यह वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर पुनः छूट देने के लिए तैयार होता है

37. **वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)** : यह वह राशि है जिसे बैंक को नकदी, सोना या अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है।

38. **नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)** : बैंकों को अपनी जमाराशि का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखना होता है। इसे सीआरआर के नाम से जाना जाता है।

39. **मौद्रिक नीति** : यह केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिए निर्धारित वृहद आर्थिक नीति है।

40. **पूंजी बाजार** : यह एक वित्तीय बाजार है जिसमें दीर्घकालिक ऋण या इक्विटी समर्थित प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है।

41. **विमुद्रीकरण** : यह किसी मुद्रा इकाई को वैध मुद्रा के रूप में उसकी स्थिति से वंचित करने का कार्य है। यह तब होता है जब राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन होता है

42. **व्यापार संतुलन** : दो देशों के बीच विनिमय की गई वस्तुओं के मूल्यों के बीच संतुलन। यह केवल व्यापारिक वस्तुओं या दृश्यमान वस्तुओं का व्यापार है

43. **भुगतान संतुलन** : दो देशों के बीच आदान-प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के बीच संतुलन। यह दृश्यमान और अदृश्य दोनों प्रकार की वस्तुओं का व्यापार है।

44. **अवमूल्यन** : इसका अर्थ है सोने या अन्य मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में आधिकारिक कमी।

45. **क्रय शक्ति** : क्रय शक्ति किसी मुद्रा का मूल्य है जिसे एक इकाई मुद्रा द्वारा खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है

46. **विदेशी मुद्रा** : किसी अन्य देश की मुद्रा।

47. **विनिमय दर** : वह दर जिस पर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में विनिमय किया जाता है।

48. **स्थिर विनिमय दरें** : एक विनिमय दर जो मौद्रिक प्राधिकारियों द्वारा एक संकीर्ण दायरे में रखी जाती है।

49. **लचीली विनिमय दरें** : लचीली विनिमय दरें खुले बाजार में मुख्यतः निजी लेन-देन द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती हैं, तथा वे अन्य बाजार मूल्यों की तरह दिन-प्रतिदिन बदलती रहती हैं।

50. **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** : किसी बहुराष्ट्रीय उद्यम द्वारा किसी विदेशी देश में किया गया निवेश तथा किसी विदेशी देश में किया गया निवेश जिसमें प्रबंधन में कुछ हद तक नियंत्रण और भागीदारी शामिल होती है।

51. **विशेष आहरण अधिकार** : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक आरक्षित मुद्रा जो सदस्य देशों के मौजूदा मुद्रा भंडार के पूरक के रूप में कार्य करती है।

52. **मुक्त व्यापार क्षेत्र** : एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक व्यापार ब्लॉक शामिल है जिसके सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे समझौतों में व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए कम से कम दो देशों के बीच सहयोग शामिल होता है।

53. **आनुपातिक कर** : कर आधार पर ध्यान दिए बिना कर एक ही दर पर लगाया जाता है

54. **प्रगतिशील कर** : कर आधार (आय) में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ जाती है

55. **प्रतिगामी कर** : गरीबों पर उच्च दर से कर लगाया जाता है और अमीरों पर कम दर से कर लगाया जाता है

56. **आंतरिक सार्वजनिक ऋण** : सरकार द्वारा नागरिकों से या देश के विभिन्न संस्थानों से लिया गया ऋण

57. **बाह्य सार्वजनिक ऋण** : विदेश से या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लिया गया ऋण

58. **राजकोषीय नीति** : सरकार की राजस्व और व्यय प्रक्रिया से संबंधित नीति

59. **सार्वजनिक व्यय** : लोगों की सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों जैसे सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए व्यय को सार्वजनिक व्यय के रूप में जाना जाता है।

60. **बजट** : यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो सरकार की आय और व्यय को दर्शाता है

61. **संतुलित बजट** : सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है। इसे संतुलित बजट कहते हैं।

62. **घाटे का बजट** : सरकार के प्रत्याशित राजस्व और लक्षित व्यय के बीच का अंतर

63. **अधिशेष बजट** : वह बजट अधिशेष बजट होता है जब वर्ष का अनुमानित राजस्व प्रत्याशित व्यय से अधिक होता है।

64. **शून्य आधारित बजट** : शून्य आधारित बजट वह बजट है जो बजट इतिहास के बजाय दक्षता और आवश्यकता के आधार पर धन आवंटित करता है। यह बजट बनाने की एक विधि है जिसमें सभी खर्चों को उचित ठहराया जाना चाहिए और प्रत्येक नई अवधि के लिए अनुमोदित किया जाना चाहिए।

65. **कॉल मनी/नोटिस मनी** : इस बाजार में एक दिन के लिए उधार दिया गया पैसा कॉल मनी कहलाता है और अगर यह एक दिन से अधिक हो तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। नोटिस मनी का मतलब 2-14 दिनों के लिए धन उधार लेना और देना है।

66. **प्रत्यक्ष कर** : प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति की आय और संपत्ति पर लगाया जाता है तथा सीधे सरकार को दिया जाता है।

67. **अप्रत्यक्ष कर** : अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने पर लगाया जाता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भुगतान किया जाता है।

68. **लेसेज-फेयर** : लेसेज-फेयर अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है जो अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है

69. **टोबिन टैक्स** : अल्पावधि पूंजी मुद्रा लेनदेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर कर। कर का बोझ लेनदेन की अवधि के व्युत्क्रमानुपाती होता है

अर्थव्यवस्था एक लाइनर

- भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में पारित किया गया था।
- एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है
- एसएलआर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। एसएलआर का मतलब है वैधानिक तरलता अनुपात
- मई 2017 से अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की गणना के लिए आधार वित्तीय वर्ष 2011-12 है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। हालाँकि, यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 17% ही योगदान देता है।
- एक आर्थिक स्थिति जब एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं उसे मोनोप्सनी कहा जाता है
- वित्तीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसके द्वारा अर्जित कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, जिसमें उधार से प्राप्त धन शामिल नहीं होता
- कीमत में वृद्धि से उपभोक्ता अधिशेष में कमी आएगी
- ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे बजट घाटा कहा जाता है
- अवसर लागत का सिद्धांत गॉटफ्रीड हैबरलर द्वारा दिया गया है।
- जब आउटपुट शून्य के बराबर होता है, तो परिवर्तनीय लागत शून्य होती है। परिवर्तनीय लागत एक कॉर्पोरेट व्यय है जो उत्पादन आउटपुट के अनुपात में बदलता है।
- पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि से राजकोषीय घाटा होता है
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष 2006 में पारित किया गया था
- भारत का केंद्रीय बजट भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद की लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है
- सूक्ष्म अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है
- हायर एंड फायर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नीति है
- बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती
- जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस) को पहली बार 2005-06 में भारतीय बजट में पेश किया गया था।
- भारतीय रुपए का प्रतीक उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया है
- आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है
- भारत में मुद्रास्फीति के दो मुख्य संकेतक थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं।

- राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) की जिम्मेदारी है
- नई जीडीपी श्रृंखला बाजार मूल्य के आधार पर जीडीपी की गणना करती है
- प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी
- भारतीय आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है
- सॉफ्टवेयर उद्योग मौसमी बेरोजगारी से प्रभावित नहीं होता
- RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पूर्ण रूप है
- किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापी जाती है
- फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था
- डीडी को बैंकर चेक कहा जाता है
- बैलेंस शीट परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्शाती है जिसमें वास्तविक खाता और व्यक्तिगत खाता शामिल होता है।
- 'कैपिटल एंड ग्रोथ' जॉन रिचर्ड हिक्स द्वारा लिखित
- जीडीपी किसी देश की वित्तीय सेहत का सूचक है
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को जीएसटी लागू किया
- भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा वर्ष 1991 में की गई थी
- एक रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं
- तीसरी पंचवर्षीय योजना को "गाडगिल योजना" के नाम से भी जाना जाता है
- भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है।
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), 2 अप्रैल 1990 को स्थापित
- भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं
- आय असमानता विकसित और गैर-विकसित दोनों देशों में गरीबी का प्रमुख निर्धारक है
- GATT, WTO का पुराना नाम था
- गोल्डन हैंडशेक योजना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़ी है
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 189 देशों का संगठन है
- चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और शून्य शुद्ध विदेशी सहायता का उद्देश्य घोषित किया गया

- ब्रेंट इंडेक्स हल्के कच्चे तेल के मूल्य स्तरों से जुड़ा हुआ है
- 12 जुलाई 1982 को ARDC का NABARD में विलय कर दिया गया
- दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी
- अल्पकालिक वित्त आमतौर पर 12 महीने तक की अवधि के लिए होता है
- 'प्लांड इकॉनमी फॉर इंडिया' एम. विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी

ACS
AIM CIVIL SERVICES
WE CREATE BUREAUCRATS
WITH IGNITED MINDS